● वर्ष : 04 ● अंक : 269

● गाजियाबाद, गुरुवार 19 फरवरी 2026

● पृष्ठ-6 ● मूल्य : दो रूपये

● RNI No - UPHIN/2022/84480

E-mail: swastiksaharanews@gmail.com

www.swastiksahara.com

विश्व एक महान पुस्तक है जिसमें वे लोग केवल एक ही पृष्ठ पढ़ पाते हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते

नई दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और एनसीआर में सर्वाधिक प्रसारित

स्वास्तिक सहारा

गाजियाबाद से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

'पायजामा का नाड़ा खोलना बलात्कार की कोशिश'

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2025 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश के आरोपों को कम गंभीर अपराध माना गया था। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक महिला के ब्रेस्ट को पकड़ने, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ने और उसे पुलिया के नीचे खींचने जैसे कथित कामों को गलत तरीके से सिर्फ 'तैयारी' माना था, न कि रेप करने की 'कोशिश'। ऐसा करते हुए, टॉप कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को भी स्वीकार कर लिया है और आरोपी दोनों के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 18 के साथ IPC की धारा 376 के तहत रेप की कोशिश के आरोपों पर कासगंज के स्पेशल जज (POCSO) द्वारा जारी किए गए ओरिजिनल समन को बहाल कर दिया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी, भोपाल से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने को भी कहा है। यह कमेटी सेक्सुअल ऑफेंस और दूसरे कमजोर मामलों से निपटने के दौरान जजों और ज्यूडिशियल प्रोसेस में 'सेंसिटिविटी और कम्पैशन पैदा करने' के मकसद से ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाएगी। कोर्ट ने कहा कि कमिटी यह काम तीन महीने के अंदर पूरा कर लेगी। रेप की कोशिश के मामले में, टॉप कोर्ट इलाहाबाद लठउ से सहमत नहीं था और कहा कि असल आरोप तैयारी से कहीं ज्यादा थे।

टॉप कोर्ट ने कहा इन आरोपों को सिर्फ.देखने से ही इस बात में जरा भी शक नहीं रह जाता कि आरोपी लोग IPC की धारा 376 के तहत उस पर जुर्म करने के पहले से तय इरादे से आगे बढ़े थे। कोर्ट ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर नाबालिग पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर ले गए, एक पुलिया के पास रुके, उसे घसीटा और उसके साथ गलत हरकतें कीं।

जुर्म इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि पीड़िता की चीखें सुनकर गवाह मौके पर पहुँच गए थे।

मां-भाई की आंखों में मिर्च झोंककर युवती का अपहरण, पुलिस की पूरे जिले में नाकाबंदी

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पुणे में दो लोगों ने 21 साल की एक लड़की को किडनैप कर लिया, जब वह अपनी मां और भाई के साथ थी। इस पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और विरोध प्रदर्शन किया। कल रात पुणे जिले में पुणे रूरल पुलिस के तहत भिगवान पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया।

पुणे रूरल पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, गणेश बिरादर ने कहा कि आरोपियों की पहचान जहीर हारून शेख और अयान हारून शेख के तौर पर हुई है। उन्होंने अपनी बाइक रोकी और पीड़िता की मां और भाई की आंखों में लाल चटनी फेंककर उसे किडनैप कर लिया। घटना के बाद आरोपियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कल रात भिगवान पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया है... इस मामले में, जहीर हारून शेख और अयान हारून शेख नाम के दो युवकों ने कथित तौर पर एक बाइक रोकी और 21 साल की एक लड़की की मां और भाई की आंखों में लाल चटनी फेंक दी, जो उसके साथ थे। इसके बाद उन्होंने 21 साल की लड़की को किडनैप कर लिया। घटना के बाद, पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई है, कई टोल चेकपॉइंट पर निगरानी बढ़ा दी गई है, और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। इस घटना से लोकल लोगों में गुस्सा है। मंगलवार रात को लोग सड़कों पर उतर आए और पुणे-सोलापुर हाईवे पर प्रोटेस्ट किया, और तुरंत एक्शन लेने और आरोपी को अरेस्ट करने की मांग की।

मायावती की हुंकार, बोलीं- हमें सत्ता से दूर रखने की साजिश

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने बुधवार को अपने समर्थकों को बीएसपी को सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा रची जा रही तीव्र साजिशों और हथकंडों के प्रति आगाह किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने राज्य और देश भर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सभी अनुयायियों से आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंबेडकरवादी आंदोलन को एकजुट करने और मजबूत करने का आ'ान किया।

मायावती ने कहा कि जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमारे विरोधी हमें सत्ता से दूर रखने और हमारे खिलाफ साजिश रचने के और भी अधिक प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के सभी अंबेडकरवादियों को आत्मसम्मान प्राप्ति के लिए डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आंदोलन को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए। इससे पहले, उन्होंने पार्टी को कमजोर करने की साजिशों का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कार्यकताओं को इन साजिशों के प्रति सतर्क किया जाएगा।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बसपा कार्यकताओं की बैठक से पहले, मायावती ने कहा कि पार्टी का ध्यान गरीबों, दलितों, आदिवासी लोगों, पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर केंद्रित किया जाएगा। बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। पार्टी कार्यकताओं को दिशा-निर्देश देने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है... चल रहे एसआईआर अभ्यास के कारण पार्टी के काम में देरी हुई है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पार्टी सदस्यों को बसपा को कमजोर करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा रची जा रही नई रणनीति और साजिशों के प्रति सतर्क किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, इस बैठक में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों और अन्य कामकाजी लोगों की दयनीय और खराब स्थिति की ओर ध्यान दिलाया जाएगा, जो केंद्र और राज्य सरकारों के तहत मौजूदा सरकारों के साथ-साथ पिछली सरकारों के तहत भी बनी हुई है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां बसपा 2022 के चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद वापसी करने की कोशिश करेगी। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा, जो कभी राज्य में सत्ता में थी, 2022 के चुनावों में सिर्फ एक सीट तक सिमट गई थी।

बुलडोजर से माफिया साफ, ब्रह्मोस से दुश्मन

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनाए सरकार के काम

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को राज्य की शक्ति का प्रतीक बताया, जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क सहित तीव्र अवसंरचना विकास और माफिया तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बुलडोजर और ब्रह्मोस एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर उन लोगों की इच्छाशक्ति को दशार्ता है जो राज्य में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं।

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में यूपी सीएम ने इसे भारत की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बताया। विरोधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास करता है, तो देश निर्णायक जवाब देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की।

उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बराबरी भी नहीं कर सकता।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नपिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने एक नई यात्रा शुरू की है। देश और दुनिया इस बात को स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। दुर्भाग्य से, संकीर्ण एजेंडा चलाने वाली सरकारों ने राज्य के भविष्य और यहां की जनता के साथ समझौता किया है। उन्होंने राज्य को अराजकता, अव्यवस्था और अपराध का गढ़ बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि दो इंजन वाली सरकार की स्पष्ट नीतियों, इरादों और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण हमने उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में एक बाधा से एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में बदल दिया है। उत्तर प्रदेश अब राजस्व घाटे से राजस्व अधिशेष की ओर बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश में 21 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है, जिनमें से 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सात साल से अधिक की सजा वाले मामलों में अब फोरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य है, और 12 ग्रेड ए फोरेंसिक प्रयोगशालाएं पहले से ही कार्यरत हैं।

शाहपुर कंडी बांध से पाकिस्तान को झटका, रावी नदी का पानी अब सींचेगा भारत के सूखे खेत

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। सिंधु जल संधि के निलंबन की चचाओं के बीच, भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा रणनीतिक झटका देने की तैयारी पूरी कर ली है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सीमा पर स्थित शाहपुर कंडी बांध का निर्माण कार्य अब पूर्णता की ओर है, जिसके बाद रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जाने के बजाय पूरी तरह भारत में ही रुक जाएगा। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की है। राणा ने कहा कि डैम का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद, पाकिस्तान जाने वाला पानी कठुआ और सांबा जिलों की ओर मोड़ दिया जाएगा, जो सूखे से प्रभावित इलाके हैं। लगभग पांच दशक पहले 1979 में, शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट की कल्पना रावी नदी के पाकिस्तान में बहाव को रेगुलेट करने और पंजाब और ख-ङ में सिंचाई के मकसद से इसका इस्तेमाल करने के लिए की गई थी। इसका शिलान्यास 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन पंजाब और जम्मू-कश्मीर सरकारों के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों की वजह से इसे बनाने में देरी हुई। 2008 में इसे एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर मान्यता मिली और अब यह डैम 2,715.70 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ आगे बढ़ रहा है।

पठानकोट जिले में रावी नदी पर, रंजीत सागर डैम से 11 किमी० नीचे और माधोपुर हेडवर्क्स से 8 किमी० ऊपर की तरफ, यह प्रोजेक्ट सिंचाई और बिजली बनाने के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।

राज्यसभा चुनाव का ऐलान, 10 राज्यों की 37 सीटों पर 16 मार्च को होगी वोटिंग

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कर दी है। ये सीटें अप्रैल 2026 में विभिन्न तारीखों पर खाली हो रही हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, इन सीटों को भरने के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। चुनाव 10 राज्यों: महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार में होंगे। मौजूदा सदस्य इस साल रिटायर हो रहे हैं, इसलिए चुनाव जरूरी हो गए हैं।

राज्यसभा की सबसे ज्यादा 7 सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में होंगे, जबकि तमिलनाडु में 6 और पश्चिम बंगाल और बिहार में छह-छह सीटें खाली हो रही हैं। ओडिशा में 4 सीटें खाली होंगी। असम में 3 सीटों पर चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 सीटों पर चुनाव होंगे, और तेलंगाना में भी। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव होगा

महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम कोटा खत्म, सरकार ने 10 साल पुराना रिजर्वेशन का फैसला पलटा

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के पहले के कदम को रद्द कर दिया है।

यह कोटा मूल रूप से 2014 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था। हालांकि, कानूनी अड़चनों के कारण यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर सभी संबंधित फैसले और सर्कुलर वापस ले लिए हैं। 2014 में राज्य सरकार ने SBC-A (स्पेशल बैकवर्ड क्लास-A) नाम की एक स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के तहत मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया था। यह कोटा सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू होना था। इस फैसले के आधार पर, एलिजिबल कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफि केट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफि केट भी दिए जा रहे थे। ऑर्डिनेंस के आने के तुरंत बाद इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 14 नवंबर, 2014 को हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्टे लगा दिया था। बाद में, ऑर्डिनेंस 23 दिसंबर, 2014 की डेडलाइन से पहले कानून नहीं बन पाया। इस वजह से, यह अपने आप लैप्स हो गया।

इस फैसले से अब क्या बदलेगा?

- 5% मुस्लिम रिजर्वेशन अब ऑफिशियली कैंसल माना जाएगा।
- इस कैटेगरी के तहत कोई नया कास्ट या वैलिडिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
- कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में 5% कोटे के तहत एडमिशन नहीं दिए जाएंगे।
- इस रिजर्वेशन से जुड़े पिछले सभी सरकारी ऑर्डर अब वैलिड नहीं होंगे।

फ्यूचर वॉर की तैयारी: इंडियन आर्मी की 'किल चेन' अब एआई से होगी और भी घातक

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। इंडियन आर्मी ने बुधवार को भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान इंडियन आर्मी के लिए इंजीनियरिंग सपोर्ट: किल चेन को स्मार्ट बनाना पर एक फोकस्ड सेमिनार किया। इसमें सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एकेडमिया को एक साथ लाया गया ताकि यह देखा जा सके कि अकपुराने प्लेटफॉर्म्स के स्मार्टाइजेशन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और अकइनेबल्ड लॉजिस्टिक्स के जरिए इक्विपमेंट की तैयारी को कैसे बढ़ा सकता है, जिससे किल चेन में ऑपरेशनल प्रिसिजन, वेलोसिटी और मिशन इफेक्टिवनेस में सुधार हो सके। मुख्य भाषण लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार साहनी, DG EME ने दिया, जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए अकका इस्तेमाल करके ज्यादा शार्प ऑपरेशनल प्रिसिजन हासिल करने के मौकों पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सेंसर डेटा के बड़े वॉल्यूम को एक्शनेबल इनसाइट्स में बदला, नए खतरों का अनुमान लगाया और पुराने वेपन सिस्टम्स को इंटेलिजेंट, डेटा-इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स में अपग्रेड किया। उन्होंने ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स को एनर्जेटिक बनाने के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव इंटरवेंशन्स के जरिए इंजीनियरिंग सपोर्ट में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया और भविष्य की लड़ाइयों में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स में अकके इंटीग्रेशन पर चर्चा की। चर्चा चार मुख्य थीम पर हुई, जिसमें सेंसर के जरिए पुराने प्लेटफॉर्म का स्मार्टाइजेशन, मजबूत डेटा पाइपलाइन, एनालिटिक्स और अक लेयर, अकइनेबल्ड प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव मेंटेनेंस ताकि फेलियर का अंदाजा लगाया जा सके और रिपेयर साइकिल को ऑप्टिमाइज किया जा सके, खास एआई टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल ट्विन्स, ऑपरेशनल माहौल में डिप्लॉयमेंट के लिए एनोमली डिटेक्शन और सिक्योर एज एनालिटिक्स, और रिसर्च को मिलिट्री जरूरतों के साथ जोड़ने और स्केलेबल, सिक्योर और मिशन के लिए तैयार अकसॉल्यूशन देने के लिए मजबूत इंडस्ट्री एकेडमिया सिनर्जी शामिल हैं। मुख्य स्पीकर में टाटा एलेक्सी के श्री बिस्वजीत बिस्वास, डेलॉइट इंडिया के श्रीराम अनंतशयनम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर शशिकुमार गणेशन शामिल थे, जिन्होंने मिशन क्रिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए स्केलेबल अकआर्किटेक्चर, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, रिलायबिलिटी मॉडलिंग और एप्लाइड अकपर अपनी राय शेयर की। सेमिनार में यह देखा गया कि अक इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स सिस्टम में इंटेलिजेंस को एम्बेड करके, इक्विपमेंट की उपलब्धता और ऑपरेशनल तैयारी को ऑपरेशनल इंटेंट के साथ जोड़कर, डिटेक्शन और डिप्लॉयमेंट से लेकर रिकवरी और रिडिप्लॉयमेंट तक किल चेन के हर स्टेज को कैसे मजबूत कर सकता है। इसमें एम्बेडेड सेंसर, अक-इनेबल्ड कंडीशन मॉनिटरिंग और रियल-टाइम एनालिटिक्स के जरिए इन-सर्विस प्लेटफॉर्म के स्मार्टाइजेशन पर जोर दिया गया, ताकि बिना ज्यादा कैपिटल खर्च के भरोसा बढ़ाया जा सके। साथ ही, डाउनटाइम कम करने, रिपेयर साइकिल को तेज करने और ऑपरेशनल टेम्पो बनाए रखने के लिए अक-ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स और प्रेडिक्टिव अलर्ट भी दिए गए।

दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन: फैमिली ट्रैवल की आड़ में हेरोइन तस्करी, 7.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दिल्ली-एनसीआर में भोपुरा बॉर्डर के पास एक इंटरस्टेट हेरोइन कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस कार्टेल से 7.5 करोड़ रुपये की 1.504 ॅ हेरोइन जब्त की गई है। साथ ही, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों में एक पति-पत्नी भी शामिल हैं। ये लोग फैमिली ट्रैवल की आड़ में टैक्सी में ड्रग्स ले जा रहे थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, पति-पत्नी और ड्रग्स लेने वाले समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कपल ने फैमिली ट्रैवल की आड़ में टैक्सी में हेरोइन ले जाई और आम लोगों में घुल-मिलकर रिस्क से बच गए। इससे वे बड़ी मात्रा में ड्रग्स को राज्य के बॉर्डर पर ले जाते समय शक से बच गए।

1.504 किग्रा० हेरोइन की जब्ती, जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपये है, इस इलाके में ड्रग तस्करी को रोकने में एक बड़ी कामयाबी है। यह ऑपरेशन दिल्ली-ठउफइलाके में भोपुरा बॉर्डर के पास किया गया। अभी तस्करी के सोर्स का पता लगाने, कार्टेल के दूसरे सदस्यों की पहचान करने और सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैप करने के लिए जांच चल रही है। हाल ही में, दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने दो अफगान नागरिकों, अब्दुल खालिक नूरजई और गुलाम हजरत मिर्जाले को 7.6 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई, जो ड्रग की कमर्शियल क्वांटिटी है।

स्पेशल जज मनु गोयल खरब की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने हर दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दुर्घटना की संभावना को न्यून करने एवं रोक लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

सड़कों पर सुरक्षात्मक उपायों में किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं: रविंद्र कुमार मॉदड़

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जनपद में दुर्घटना की संभावना को न्यून करने एवं रोक लगाने के उद्देश्य, सड़कों को गड्ढा मुक्त एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉदड़ की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में जनपद की सड़कों की वर्तमान स्थिति, गड्ढा मुक्ति अभियान, दुर्घटना सम्भावनों पर रोक लगाने की प्रक्रिया की प्रगति तथा शेष कार्यों की समीक्षा की गई।

बताते चलें कि हाल ही में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एक निमार्णाधीन मॉल के बेसमेंट में जलभराव के कारण हुई मृत्यु की घटना के दृष्टिगत जनपद में निमार्णाधीन मॉल एवं बहुमंजिला भवनों / इमारतों, सडकों पर खुले गढे, तालाब, पोखर/सीवर, क्षतिग्रस्त डिवाइडर, पुल व अन्य सभी प्रकार के दुर्घटना संभावित क्षेत्र आदि को चिन्हित कर सूचना उपलब्ध कराने तथा दुर्घटना की संभावना को न्यून करने के सम्बंध में पूर्व में भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में यह बैठक आहूत हुई।

बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की अधिकांश सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। शेष 83 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां शीघ्र ही मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाएगा। कई स्थानों पर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शेष स्थानों पर भी निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। चिन्हित 83 स्थानों में लोक निर्माण विभाग झ 20 स्थान, नगर निगम गाजियाबाद झ 26 स्थान, यूपीसीडा झ 5 स्थान, नगर पालिकाएं झ 26 स्थान, आवास विकास झ 01 स्थान, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण झ 05 स्थान हैं। जिलाधिकारी महोदय ने सभी विभागों को स्पष्ट एवं कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों की मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी भी सड़क पर विभागीय लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी विभागों को यह निर्देश दिये गये कि अपने क्षेत्रान्तर्गत पुनः ऐसी जगहों का चिन्हांकन कर लिया जाये जहां दुर्घटना होने की संभावना रहती है तथा उन जगहों पर पर इस प्रकार के पर्याप्त उपाय किये जाये कि इस प्रकार की दुर्घटना किसी भी दशा में न होने पाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए। साथ ही, जनता से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। बैठक में एडीएम सिटी विकास कश्यप सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और सभी विभागाधिकारियों ने जनपद को गड्ढा मुक्त एवं सुरक्षित बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का आश्वासन दिया।

● विभागीय लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉदड़

जेईई मेन में नेहरू वर्ल्ड स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन रहा शानदार

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। नेहरू वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने जेईई मेन परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नामरोशन किया है। सोमवार 16 फरवरी 2026 को घोषित परिणाम में विद्यालय के 40 प्रतिशत छात्रों ने 99.70 से 90.00 परसेंटाइल के बीच अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इस शानदार उपलब्धि से विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण, विद्यार्थी और अभिभावकों में हर्ष का माहौल है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित परीक्षा में विद्यालय के छात्र अभिनव त्यागी ने 99.70 परसेंटाइल के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उनके अलावा उर्जिता त्रिपाठी ने 99.57, अनन्या शर्मा ने 99.18 और शांतनु अग्रवाल ने 99.02 परसेंटाइल प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। दानिश लोनी (98.33), झंकार बत्रा (98.15), आराध्या भारद्वाज (97.70) और प्रियांश गर्ग (97.58) सहित अनेक छात्रों ने 95 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

विद्यालय के कुल 30 छात्रों ने 90 से अधिक परसेंटाइल प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के बल पर सफलता प्राप्त की जा सकती है।

प्रबंधन ने कहा कि यह उपलब्धि विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की लगन का परिणाम है। गाजियाबाद स्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों ने विश्वास जताया कि आगामी अप्रैल में होने वाली जेईई मेन की अगली परीक्षा में भी छात्र बेहतर प्रदर्शन कर विद्यालय और जनपद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे।

परिवहन विभाग, गाजियाबाद कार्यालय में परिवहन मेले का आयोजन

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायिक वाहनों में भी एकमुश्त कर व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था तकनीकी रूप से वाहन पोर्टल पर पूर्ण रूप से लाइव कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत भाड़े अथवा पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटरसाइकिल, तिपहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब, प्रयोजन यान, माल वाहन, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक सेवायान सहित विभिन्न श्रेणियों के परिवहन यानों को सम्मिलित किया गया है। इस एकमुश्त कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार कर भुगतान की जटिल, समय-साध्य प्रक्रिया से राहत प्रदान करना, प्रशासन को सरल एवं पारदर्शी बनाना, अधिकाधिक गैर-परिवहन यानों को परिवहन यानों में परिवर्तित करना तथा विभागीय राजस्व संग्रह प्रणाली को अधिक सुदृढ़ करना है। परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 3000 किलोग्राम से अधिक तथा 7500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले वाहनों (मिनी ट्रक आदि) के लिए वाहन के क्रय मूल्य का 6 प्रतिशत एकबारीय कर के रूप में निर्धारित किया गया है।

भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। भारतीय जनता पार्टी महानगर गाजियाबाद द्वारा 18 फरवरी 2026 को कविनगर स्थित रामलीला मैदान, जानकी भवन में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक चले इस प्रशिक्षण वर्ग में महानगर सहित तीनों विधानसभाओं के 20 मंडलों से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर संगठन सुदृढ़ीकरण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रस्तावना सत्र से हुआ, जिसमें 'गुरु देव भवः' विषय पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। वक्ताओं ने संगठनात्मक जीवन में अनुशासन, समर्पण एवं वैचारिक स्पष्टता को कार्यकर्ता निर्माण का मूल आधार बताया। इसके उपरांत 'पंच परिवर्तन' विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए सामाजिक, वैचारिक एवं संगठनात्मक परिवर्तन की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया गया।

महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित यह वर्ग संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित एवं जागरूक कार्यकर्ता ही संगठन की वास्तविक शक्ति होते हैं और आने वाले अभियानों को सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

मुख्य वक्ता एवं प्रशिक्षण अभियान के क्षेत्रीय सह संयोजक नरेश तोमर ने बताया कि 7 मार्च से 14 अप्रैल तक एक माह का विशेष प्रशिक्षण एवं प्रवास अभियान चलाया जाएगा। इस अवधि में महानगर सहित तीनों विधानसभाओं के 20 मंडलों में 24 घंटे का प्रवास कार्यक्रम आयोजित कर बूथ स्तर तक कार्यशालाएं संपन्न कराई जाएंगी, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त किया जा सके।

सांसद अतुल गर्ग ने 'पंच परिवर्तन' विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में आईजीआरएस की समीक्षा बैठक संपन्न

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गौतमबुद्धनगर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में असंतुष्ट फीडबैक तथा स्पेशल क्लोज से संबंधित प्रकरणों की विभागवार एवं प्रकरणवार गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि असंतुष्ट फीडबैक के अंतर्गत डीआईओएस, डीपीओ, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि विभागों से संबंधित प्रकरण लंबित एवं गुणवत्ताहीन निस्तारण की श्रेणी में पाए गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित उच्चाधिकारियों एवं शासन को प्रेषित किया जाएगा, ताकि विषय का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन विभागों में असंतुष्ट फीडबैक की संख्या अधिक पाई जाएगी अथवा बिना उचित श्रेणी चयन किए प्रकरणों को स्पेशल क्लोज किया जाएगा, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा आख्या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ ने सुनी जनता दर्शन में जन समस्याऐं

जनता का उत्पीड़न किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं: जिलाधिकारी

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान जनसुनवाई की गयी। जन सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, जीडीए, नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से सम्बंधित प्रार्थना/शिकायती पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिकारियों को शासन के मंशा अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने तथा जमीन से संबंधित समस्या को पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ससमय सुनिश्चित कराएं जाने के निर्देश दिया गया। जनता दर्शन में निरंतर प्राप्त होने वाली शिकायतों, समस्याओं और निवेदनों दिव्यांगजन कल्याण विभाग, शस्त्र लाईसेंस (विरासत), नियोजन विभाग (फैमिली आईडी), यू0पी0नेडा, पीएम सूर्य घर योजना, अवैध कब्जा/भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान आदि के निस्तारण एवं निवारण के क्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देशित दिए गये। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि उक्त सभी कार्य युद्ध स्तर पर किये जाएं, उक्त से सम्बंधित किसी भी व्यक्ति को असुविधा का सामना ना करना पड़ें। ऐसा कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जावेगा जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएं। जनता का उत्पीड़न किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं हैं। जनसुनवाई के दौरान एडीएम ई ज्योति मौर्य, एडीएम एल/ए अवनीश, एडीएम सिटी विकास कश्यप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कासना प्राथमिक विद्यालय में VHSND सत्र का सफल आयोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गौतमबुद्धनगर। कासना प्राथमिक विद्यालय में Village Health Sanitation and Nutrition Day (VHSND) सत्र का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना तथा समुदाय में पोषण एवं टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। सत्र के दौरान गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। गर्भवती महिलाओं का वजन मापन, हीमोग्लोबिन जांच, नियमित टीकाकरण तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निर्धारित टीके लगाए गए। डीसीपीएम यूनिसेफ की टीम से आशीष सक्सेना द्वारा सत्र का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त CDPO संध्या सोनी ने भी केंद्र पर पहुंचकर VHSND गतिविधियों का अवलोकन किया। उनके निर्देशन में गर्भवती महिलाओं को एल्बेंडाजोल दवा सेवन के महत्व की जानकारी दी गई तथा बच्चों के टफ टीकाकरण के संबंध में जागरूक किया गया। उपस्थित लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय में स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के प्रति सकारात्मक संदेश प्रसारित किया गया। यह पहल मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डी आर कान्वेंट स्कूल दादरी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, 22 फरवरी को नोएडा हाट में मेगा शिविर

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

नई दिल्ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर अतुल श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय/नोडल अधिकारी (मेगा साक्षरता शिविर) विरेक अग्रवाल की अध्यक्षता में विगत दिवस डी आर कान्वेंट स्कूल दादरी के प्रांगण में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में महिला कल्याण विभाग की प्रतिनिधि सुनीता द्वारा विभाग की प्रमुख योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रश्मि त्रिपाठी द्वारा मिशन प्रेरणा, डीबीटी योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, मिड डे मील, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आपरेशन कायाकल्प आदि योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय/नोडल अधिकारी (मेगा साक्षरता शिविर) विरेक अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निदेर्शानुसार 22 फरवरी 2026 को प्रात 10:00 बजे से नोएडा हाट, सेक्टर 33ए, नोएडा में मेगा विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। मेगा शिविर में विभिन्न विभागों के लगभग 44 स्टाल लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी आमजन को उपलब्ध कराई जाएगी।

जनपद न्यायाधीश ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गौतमबुद्धनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर के तत्वावधान में जनपद में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से आज जिला न्यायालय परिसर से मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त प्रचार वाहन को माननीय जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जनपद के समस्त संबंधित न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। प्रचार वाहन के माध्यम से 22 फरवरी 2026 को शिल्प हाट, सेक्टर 33ए, नोएडा में आयोजित होने वाले मेगा साक्षरता शिविर एवं सेवा शिविर तथा 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी भी जनसामान्य तक पहुंचाई जाएगी। प्रचार वाहन पर आकर्षक बैनर एवं विस्तृत सूचना सामग्री एवं पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में विधिक सेवाओं, लोक अदालत की विशेषताओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार के विषय में जागरूक किया जाएगा। मेगा साक्षरता शिविर एवं सेवा शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, परामर्श एवं आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं 14 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित एवं समझौता योग्य वादों का त्वरित, सुलभ एवं आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को कम समय और न्यून व्यय में न्याय प्राप्त हो सके। माननीय जनपद न्यायाधीश ने कहा कि विधिक सेवाएं प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार हैं तथा लोक अदालत न्याय प्राप्ति का सरल, त्वरित एवं प्रभावी माध्यम है।

गाजियाबाद में नगरीय निकाय योजनाओं एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मॉदड़ की अध्यक्षता में जनपद के नगरीय निकायों द्वारा संचालित विकास योजनाओं एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में नगर पालिका परिषद लोनी, मोदीनगर, खोड़ाझमक्कनपुर, मुरादनगर तथा नगर पंचायत डासना, फरीदनगर, पतला एवं निवाड़ी के अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्षगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में प्रस्तावित एवं प्रगति पर चल रहे विकास कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुत प्रस्तावों में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, जल संरक्षण, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, शैक्षिक संस्थानों का निर्माण एवं सौन्दर्यकरण, कस्तूरबा गांधी विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में आवश्यक निर्माण कार्य, पार्कों का विकास, सामुदायिक शौचालय निर्माण, कूड़ा निस्तारण व्यवस्था, नालों का निर्माण एवं स्वच्छता सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न जनहितकारी योजनाएं सम्मिलित रहीं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आगामी समय में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने एवं संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए सभी निकाय आवश्यक एहतियाती व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी निकाय के पास फॉगिंग मशीन अथवा अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके क्रय हेतु तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं, जिससे समय रहते प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों में एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर की स्थापना की आवश्यकता है, वहां भी प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि आवारा पशुओं की समस्या का सुव्यवस्थित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए जनसामान्य को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए तथा शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

फोर्टिस अस्पताल ने बचाई 9 वर्षीय बच्चे की जान, 10 दिनों से था वेंटिलेटर पर

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। फोर्टिस हॉस्पीटल ग्रेटर नोएडा के डॉक्टरों ने क्लीनिकल निर्णय और मल्टीडिसीप्लीनरी तालमेल का शानदार परिचय देते हुए, गंभीर किस्म के बोन इंफेक्शन से पीड़ित 9 वर्षीय बच्चे का सफलतापूर्वक उपचार कर उसे नया जीवनदान दिया है।इस बच्चे का इंफेक्शन इतना बिगड़ चुका था कि मरीज सेप्टिक शॉक में चला गया था और ऐसे में उसे बचाने के लिए अगले 10 दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट और इंटेंसिव केयर में रखा गया।

इस बच्चे को जब अस्पताल लाया गया तो वह लगातार बुखार, और करीब एक हफ्ते से चलने-फिरने में परेशानी महसूस होने तथा दांए पैर के निचले हिस्से तथा कूल्हे में सूजन और दर्द से जूझ रहा था।इससे पहले, 4-5 दिनों तक अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करवाने (ओपीडी और आईपीडी) के बावजूद, मरीज की हालत में कोई सुधार होने की बजाय उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। मामले की गंभीरता को भांपते हुए डॉ भरत गोस्वामी, कंसल्टेंट ऑर्थोपिडिक्स, फोर्टिस हॉस्पीटल ग्रेटर नोएडा ने एनेस्थीसिया टीम डॉ भूप सिंह, एडिशनल डायरेक्टर एनेस्थीसियोलॉजी, फोर्टिस ग्रेटर नोएडा और डॉ स्वयंभू शुभम, अटेंडिंग कंसल्टेंट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, फोर्टिस ग्रेटर नोएडा के साथ मिलकर

इमरजेंसी सर्जरी करके बच्चे की जान बचाई।

इस मामले की जानकारी देते हुए फोर्टिस हॉस्पीटल ग्रेटर नोएडा के कंसल्टेंट पिडियाट्रिक्स डॉ कुशाग्र गुप्ता ने कहा कि बच्चों में बोन इंफेक्शन तेजी से बढ़ सकता है और यदि समय पर उपचार न किया जाए तो यह जीवनघाती भी होता है।शुरूआत में ही पहचान करने, तत्काल सर्जिकल सहायता मिलने और इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट में तालमेल के चलते इस बच्चे का जीवन बचाने में सफलता मिली।

इस मामले ने एक बार फिर जटिल किस्म की पिडियाट्रिक इमरजेंसी से निपटने में मल्टीडिसीप्लीनरी टीमों के बीच आपसी तालमेल के महत्व को उजागर किया है। फोर्टिस हॉस्पीटल ग्रेटर नोएडा के कंसल्टेंट ऑर्थोपिडिक्स डॉ भरत गोस्वामी ने कहा कि हमें सर्जरी के दौरान जिस मात्रा में मवाद और इंफेक्शन दिखायी दिया उससे हमें अंदाजा हुआ कि मरीज का रोग किस हद तक आक्रामक हो चुका था।तत्काल मवाद निकालने और इंटेंसिव पोस्ट-ऑपरेटिव केयर ने इस बच्चे के जोड़ का स्थायी क्षरण होने और इंफेक्शन को घातक होने से रोक दिया।

इस मामले ने बच्चों में बोन इंफेक्शन का समय पर उपचार न करने के चलते उत्पन्न होने वाले खतरों की ओर इशारा किया है।बोन इंफेक्शन के चलते सेप्टिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोमायलिटिस, सेप्टिक शॉक तथा कई बार दीर्घकालिक विकलांगता भी पैदा हो सकती है।

इलाज के बाद यह मरीज सुरक्षित तरीके से अपने घर लौट चुका है, धीरे-धीरे स्वास्थ्यलाभ कर रहा है जो कि इस बात का प्रमाण है कि समय पर मेडिकल सहायता,एडवांस क्रिटिकल केयर और फोर्टिस हॉस्पीटल ग्रेटर नोएडा में टीमों के बीच तालमेल ने उसकी रिकवरी में योगदान दिया।

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे ग्रेटर नोएडा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। वरिष्ठ पत्रकार, ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र चंदेल के बेटे कर्ण चंदेल का लगन सगाई समारोह मंगलवार की रात सम्पन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश व देश के दिग्गज नेता और अधिकारी व समाजसेवियों समेत अन्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए।इसी कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे।इस दौरान उन्होंने कर्ण चंदेल को अपना आशीर्वाद देते हुए सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। साथ ही राज्य सभा सदस्य सुरेंद्र नागर, पूर्व मंत्री नवाब सिंह नगर, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष विमला बाथम, भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्र अध्यक्ष तेजा गुर्जर , भाजपा जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा और महानगर अध्यक्ष महेश चौहान भी शामिल हुए। ज्ञात हो कि धर्मेंद्र चंदेल बीते दशकों से पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाये हुए हैं। अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को दिशा और क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करा रहे हैं।

एमपीएल सीजन 5 का भव्य समापन, फाइनल मुकाबला महर्षि यूनिवर्सिटी नें 3 विकेट से जीता

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमयूआईटी) द्वारा आयोजित महर्षि प्रीमियर लीग (एमपीएल) सीजन 5 का भव्य समापन एक बेहद रोमांचक और यादगार फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। दिल्ली एनसीआर के इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूनार्मेंट के अंतिम दिन दर्शकों को शानदार खेल और जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। फाइनल मुकाबले में बैनेट यूनिवर्सिटी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महर्षि यूनिवर्सिटी के सामने 156 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।जवाब में महर्षि यूनिवर्सिटी की टीम ने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाते हुए 7 गेंदें शेष रहते 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली। आखिरी ओवरों

में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया था और दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन अंततः महर्षि यूनिवर्सिटी ने शानदार जीत अपने नाम की। मुकाबले में महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी मोहित ने 54 रनों की शानदार पारी खेली और साथ ही एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया। उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनिंदर सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने दोनों टीमों के खेल की सराहना की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के विश्वविद्यालय स्तरीय टूनार्मेंट युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बड़ा मंच प्रदान करते हैं। इस अवसर पर महर्षि यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि महर्षि प्रीमियर लीग वर्ष दर वर्ष अपना स्तर ऊंचा कर रहा है।

नोएडा में एनसीसी 'ए' प्रमाण पत्र की व्यावहारिक परीक्षा सम्पन्न

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) आर्मी विंग की 37 एनसीसी बटालियन, गाजियाबाद के तत्वावधान में 'ए' प्रमाण पत्र संबंधी व्यावहारिक परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। परीक्षा के दौरान कैडेटों का ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, मानचित्र पठन, फील्ड क्राफ्ट सहित विभिन्न सैन्य विषयों पर परीक्षण किया गया। इस अवसर पर कुल 45 कैडेटों ने भाग लिया, जिनमें 22 बालिका एवं 23 बालक कैडेट शामिल रहे। सभी कैडेटों ने अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया। विद्यालय में यह पहला एनसीसी प्रशिक्षण सत्र है, जिसे लेकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। वर्तमान में विद्यालय में एनसीसी की दो पलटन

संचालित हो रही हैं एक प्रथम वर्ष एवं दूसरी द्वितीय वर्ष के कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। एनसीसी कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण निशांत भारत द्वारा दिया जा रहा है। वे टैक्टिकल वेपन ट्रेनिंग के विशेषज्ञ, ट्रिगर ऑपरेटर्स अकादमी के संस्थापक तथा 'मिशन योद्धा' अभियान के तहत कैडेटों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य देश को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़, अनुशासित एवं राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पित युवा प्रदान करना है।

साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किये गये जन कवि जय प्रकाश शर्मा प्रकाश

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

वाराणसी। प्रयागराज मौलिक विचार एवं साहित्यिक सर्जना की प्रतिनिधि पत्रिका साहित्यांजलि प्रभा से प्रवर्तित साहित्यांजलि प्रकाशन प्रयागराज द्वारा इस माह का साहित्य रत्न सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार जनकवि जय प्रकाश शर्मा प्रकाश दिया गया गोविंदपुर में अपट्रान चौराहे पर स्थित शिवासिटी मान्टेसरी स्कूल के सभागार में कल शाम सम्पन्न हुए भव्य समारोह में ख्यातिलब्ध साहित्यकार डॉ शंभूनाथ त्रिपाठी अंशुल जी की अध्यक्षता और माननीय न्यायमूर्ति सुधीर नारायण के मुख्य आतिथ्य में साहित्यकार सत्कार : आपके द्वार सम्मान योजना में जनकवि को साहित्य रत्न सम्मान प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र देकर अलंकृत किया गया और इस अवसर पर इनकी

पचपनवीं कृति क्या खोया क्या पाया का लोकार्पण भी मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया।मां सरस्वती के चित्र पर मुख्य अतिथि द्वारा माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित करके सम्मान समारोह शुरू हुआ जिसमें देववाणी संस्कृत में सरस्वती वंदना गरिमा साहू ने की और डॉ राम लखन चौरसिया वागीश ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया । सभी का परिचय मासिक पत्रिका साहित्यांजलि प्रभा के सह सम्पादक रवींद्र कुशवाहा ने दिया और विवेक शर्मा सुमन ने मंचासीन अतिथियों सहित सभी उपस्थित कवियों को अंगवस्त्र और माल्यार्पण करके अभिनंदित कि रवीन्द्र कुशवाहा,राकेश मालवीय मुस्कान , आचार्य अनीस देहाती , अनिल बहोरिकपुरी , शिवम भगवती अभ्युदय सिंह , विमल राय , अशोक कुमार , डॉ ज्ञान सिंह , श्री मती सुमन शर्मा , रश्मि राधे , पंक्ति प्रकाश , पं देवी प्रसाद मिश्र वेदांती , पीयूष मिश्रा ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया । समारोह का संचालन डॉ भगवान प्रसाद उपाध्याय ने किया जिसमें आसपास के अन्य गणमान्य नागरिक भी शामिल रहे ।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा उद्योग एवं व्यापार से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक

नोएडा(स्वास्तिक सहारा)। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल (जिला गौतमबुद्ध नगर) द्वारा उद्योग एवं व्यापार से संबंधित मुद्दों एवं उनके समाधान पर एक सामूहिक बैठक का आयोजन संस्था के चेयरमैन डॉ पीयूष द्विवेदी के नेतृत्व में उनके कार्यालय सेक्टर 63 में किया गया। जिसमें संजय जैन अध्यक्ष, अमित अग्रवाल वरिष्ठ महासचिव, नरेश बंसल कोषाध्यक्ष, राहुल भाटिया महासचिव, डॉ विकास बंसल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, के.के. अग्रवाल (सीए) उपाध्यक्ष, संजय कोहली उपाध्यक्ष, सुनील वर्मा सचिव समेत व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीयों ने बैठक में सम्मिलित हो जन समस्याओं पर अपने अपने विचार रखें। व्यापार मंडल द्वारा नोएडा प्राधिकरण संबंधित, पुलिस प्रशासन संबंधित, जीएसटी डिपार्मेंट संबंधित समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं जल्दी ही व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल संबंधित विभागों से संपर्क कर समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करेगा।

नोएडा प्राधिकरण में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने जवाबदेही मजबूत करने और विभागों के बीच जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति खत्म करने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग संचालित पब्लिक हेल्थ और नोएडा ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारियां अब जोनल वर्क सर्किलों को सौंप दी गई हैं। इस बदलाव का मकसद निर्णय प्रक्रिया को तेज करना और फील्ड स्तर पर निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है। संशोधित ढांचे के अनुसार वर्क सर्किल 1 से 5 का प्रभार जीएम एसपी सिंह को सौंपा गया है, जबकि वर्क

सर्किल 6 से 10 की जिम्मेदारी जीएम एके अरोड़ा को दी गई है। एसपी सिंह पहले ट्रैफिक सेल और पब्लिक हेल्थ विभाग के साथ सिविक कार्यों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अब वे अपने क्षेत्र में स्वच्छता, सीवर रखरखाव, नालों की सफाई, खुदाई की निगरानी, सड़क बहाली और ट्रैफिक से जुड़े सिविल कार्यों की एकीकृत जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी तरह अरोड़ा को भी अपने जोन में सभी संबंधित कार्यों की समेकित जिम्मेदारी दी गई है। नई व्यवस्था में सीनियर मैनेजर और प्रोजेक्ट स्टाफ सीधे संबंधित वर्क सर्किल के जीएम को रिपोर्ट करेंगे। इससे सिंगल-पॉइंट जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। प्राधिकरण का मानना है कि इससे फाइलों के अनावश्यक आदान-प्रदान, विभागों के बीच भ्रम और निर्णय में देरी की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी। यह पुनर्गठन सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सिटी में 27 वर्षीय युवराज सिंह की मौत के बाद किया गया है। युवराज खुले ट्रेंच में गिरकर डूब गए थे। घटना के बाद बैरिकेडिंग, खुदाई के सुरक्षा मानकों और साइट मॉनिटरिंग को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया था कि ट्रेंच बिना पर्याप्त चेतावनी संकेत, रोशनी या सुरक्षा कवर के खुला छोड़ा गया था, जिससे यह हादसा हुआ। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2012 में गठित ट्रैफिक सेल और पब्लिक हेल्थ विभाग समय के साथ सिविल विभाग से अलग-अलग कार्य करते रहे। खुदी सड़कों की मरम्मत, ट्रेंच बहाली और जलभराव जैसे मामलों में फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रहती थीं, जिससे देरी और जवाबदेही का अभाव पैदा होता था।

शहर को जाममुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण ध्वस्त किये गये

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। शहर को जाममुक्त बनाने के उद्देश्य से आज नोएडा के विभिन्न जगहों पर व्यापक अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया गया। नोएडा प्राधिकरण के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार वर्क सर्किल-1 से 10 तक गठित टीमों ने सेक्टर-10, 44, 69, 72, 57, 80, 81, 82 के साथ ग्राम भूड़ा, नयागांव मंडी, फेस-2 मंडी, कैंट रोड, हौजरी कॉम्प्लेक्स और एक्सप्रेस-वे के क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा जमाए अवैध वेंडर्स, ठेली-पटरी और अन्य अनधिकृत ढांचों को मौके पर ही हटाया गया। कई स्थानों पर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर जुमार्ना, जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और जाममुक्त बनाने के लिए यह अभियान अब नियमित रुप से जारी रहेगा।

कुमुद शेखर सिंह की त्वरित कार्रवाई: 6 गिरफ्तार 5 मोटरसाइकिल वाहन सीज

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। पन्नूगंज थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा पांच मोटरसाइकिलों वाहनों को 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर अपराध एवं अवांछित तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सदर क्षेत्राधिकारी राज के कुशल मार्गदर्शन मे पन्नूगंज प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने यह कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम

भुसौलिया स्थित मैरा पाण्डेय ग्राउंड में कुछ युवक मोटरसाइकिलों के साथ केक काटकर तेज शोर-शराबा कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूचना मिलते ही थाना पन्नूगंज पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छह युवकों को हिरासत में ले लिया। उनके विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया। साथ ही मौके पर खड़ी पांच मोटरसाइकिलों वाहनों को एमपी एक्ट के तहत सीज कर दिया गया। घटना के दौरान तीन युवक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। किसान संघर्ष समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता चरण सिंह राजपूत को संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनीलम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. सुशीला ताई मोराले , राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता एड. शिवसिंह, राष्ट्रीय सचिव शशिभूषण चौहान, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुहैल कादरी, प्रदेश अध्यक्ष एड. आराधना भार्गव, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सहित प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों व

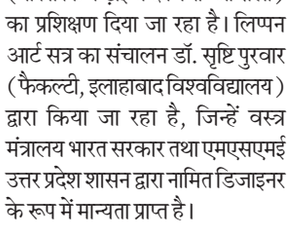

कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनीलम ने कहा कि चरण सिंह राजपूत की राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति से संगठन को वैचारिक मजबूती मिलेगी तथा किसानों-मजदूरों के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रभावी ढंग से उठाए जा सकेंगे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली पर उठे सवाल, सहकारी समिति ने लगाये गंभीर आरोप

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। पॉवर ऑफिसर्स सहकारी आवास समिति लिमिटेड ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाते हुए नोएडा में एक प्रेस वार्ता की। आरोप है कि समिति के सचिव राजबीर सिंह ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से पांच साल पहले एक एसोसिएशन का निबंधन कराया उसके बाद पांच साल बाद नाम बदल दिया। बता दे कि समिति में इस तरह के बदलाव का कोई नियम नहीं हैं।समिति के अध्यक्ष अजय कुमार बाना का कहना है कि उसकी उपविधियों में किसी भी प्रकार की आरडब्ल्यूए या एओए के गठन का

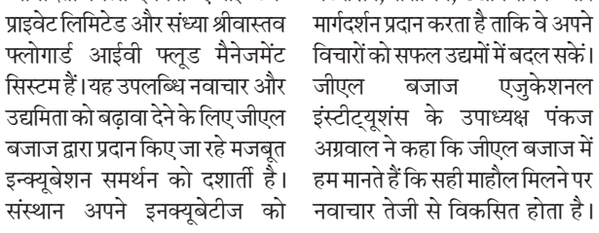

कोई प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद समानांतर संस्था का गठन नियमों के विपरीत किया गया। आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के आदेशों के अनुपालन में समिति द्वारा उक्त आरडब्ल्यूए के निरस्तीकरण हेतु प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके तहत डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि, आरडब्ल्यूए की ओर से नोटिस का जवाब देने के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 14274/2022 दायर कर दी गई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई तक निरस्तीकरण की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।

समाज कल्याण मंत्री संजय गोंड़ भिखारी बाबा आश्रम पहुंचे, पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। रामगढ़ कसारी स्थित भिखारी बाबा आश्रम पर शिवरात्रि की रात्रि में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री संजय गौड़ जा पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा भगवान शंकर का पूजन- अर्चन किया और गौशाला में जाकर गौ माता को गुड़ खिलाया।भिखारी भोले सेवा ट्रस्ट की ओर से मंत्री जी को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंत्री जी ने आश्रम की सराहना करते हुए संचालन में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। भिखारी बाबा ने बताया कि मंत्री जी की आश्रम पर आने

की इच्छा बहुत दिनों से थी। जब प्रभु का बुलावा आया तो शिवरात्रि के अवसर पर मंत्री जी का आगमन आश्रम पर हुआ। उन्होंने भगवान शंकर का पूजन-अर्चन किया, उसके बाद आश्रम के गौशाला में जाकर गौ माता को गुड़ खिलाया। मंत्री जी ने आश्रम की सराहना करते हुए कहा कि आश्रम के संचालन में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मंत्री जी का भिखारी भोले सेवा ट्रस्ट के द्वारा अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इसके अलावा साथ में पहुंचे इंजीनियर रमेश पटेल व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश पटेल का भी अंगवस्त्र देकर सम्मान किया गया।

स्वदेशी शिल्प परंपराओं को नया आयाम: वसंत कन्या महाविद्यालय में दो दिवसीय अनुभवात्मक कार्यशाला व प्रदर्शनी का शुभारंभ

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

वाराणसी। वसंत कन्या महाविद्यालय, कमच्छा में गृह विज्ञान विभाग द्वारा दो दिवसीय अनुभवात्मक कार्यशाला, प्रदर्शनी एवं बिक्री स्टॉल का शुभारंभ महाविद्यालय परिसर के कैंटीन क्षेत्र में किया गया। यह आयोजन 18 एवं 19 फरवरी 2026 को प्रतिदिन अपराह्न 4:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम विभागाध्यक्ष प्रो. संगीता देवड़िया के निर्देशन एवं प्राचार्य प्रो. रचना श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। आयोजन कौशल विकास तथा Lerning by Doingl आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक पहल है। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय पारंपरिक शिल्प विधाओं से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना तथा स्वदेशी कला परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रेरित करना है। इसमें लिप्पन आर्ट (कच्छ, गुजरात की भित्ति सज्जा कला) तथा खटवा एवं मिरर वर्क (पारंपरिक कढ़ाई व दर्पण सज्जा शैली) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लिप्पन आर्ट सत्र का संचालन डॉ. सृष्टि पुरवार (फैकल्टी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार तथा एमएसएमई उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित डिजाइनर के रूप में मान्यता प्राप्त है।

एआई इम्पैक्ट समिट में जीएल बजाज के तीन स्टार्टअप्स का चयन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। भारत मंडपम नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में जीएल बजाज सेंटर फॉर रिसर्च एंड इन्क्यूबेशन द्वारा इनक्यूबेट किए गए तीन स्टार्टअप्स का चयन किया गया हैं। यह समिट विश्व के सबसे बड़े मंचों में से एक है, जहाँ वैश्विक नेता, सीईओ, नीति निमार्ता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और उसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं। इस प्रतिष्ठित मंच पर जीएल बजाज का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन स्टार्टअप्स आदित्य त्रिपाठी एकलव्य इंडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड,

आनंदिता मिश्रा ईस्पेस एआई टेक प्राइवेट लिमिटेड और संध्या श्रीवास्तव फ्लोगार्ड आईवी फ्लूड मैनेजमेंट सिस्टम हैं। यह उपलब्धि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जीएल बजाज द्वारा प्रदान किए जा रहे मजबूत इन्क्यूबेशन समर्थन को दशार्ती है। संस्थान अपने इनक्यूबेटीज को मेंटरशिप, संसाधन, उद्योग संपर्क और मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि वे अपने विचारों को सफल उद्यमों में बदल सकें। जीएल बजाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने कहा कि जीएल बजाज में हम मानते हैं कि सही माहौल मिलने पर नवाचार तेजी से विकसित होता है।

सम्पादकीय

एआई का महाकुंभ

अब यह समय और दौर 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (एआई) का है। आगामी तीन सालों में एआई का विस्तार हजार गुना होगा और जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, परिवहन, प्रशासन और नीति–निर्माण, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान से लेकर आम आदमी और कर्मचारी तक एआई का दखल होगा और ये क्षेत्र एआई से ही संचालित होंगे। भारत एआई के बड़े और स्थापित देशों की रेस में शामिल नहीं है, लेकिन एआई की प्रतिभाएं देश में 33 फीसदी की दर से बढ़ रही हैं। करीब 69 फीसदी कंपनियां इस साल एआई में निवेश बढ़ाएंगी और 80 फीसदी कंपनियां इस नए हुनर को प्राथमिकता दे रही हैं। करीब 92 फीसदी कर्मचारी एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भारत में एआई के तीन आधिकारिक सूत्र घोषित किए गए हैं–लोग (पीपल), ग्रह (प्लैनेट), प्रगति (प्रोग्रेस)। यकीनन इनमें नैतिकता और मानवता का भाव अधिक है। लिहाजा राजधानी दिल्ली में एआई का जो पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन सजा है, उसका महत्व 'महाकुंभ' सरीखा है। इस महाकुंभ में 100 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ, 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 135 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। 20 फरवरी तक 3250 से अधिक वक्ता बोलेंगे और करीब 500 सत्र आयोजित किए जाएंगे। किसी नई प्रौद्योगिकी पर विमर्श और चिंतन–मनन के लिए यह सर्वोच्च मंच है, लिहाजा 'महाकुंभ' जैसा महत्व है। सभी हिस्सेदार, भागीदार व्यक्ति या देश एआई के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और एक पथ तय करेंगे कि एआई किस तरह मानवोपयोगी साबित हो सकती है। इतनी व्यापक चर्चा तब भी नहीं हुई, जब कम्प्यूटर हमारे बीच आया था और देश भय, खौफ में थे कि यह मानव का विकल्प साबित हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ और आज कम्प्यूटर हमारे कामकाज का बुनियादी हथियार है। बहरहाल ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया (सोल), फ्रांस (पेरिस) के बाद एआई का यह शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में जारी है। करीब 3 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। दरअसल बुनियादी चिंता एआई चिप्स, रोजगार और परिवर्तन के बाद की दुनिया को लेकर है। भारत में एआई को 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इससे मुंह के कैंसर की 86 फीसदी तक सटीक पहचान हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी, मद्रास 100 से अधिक भारतीय बोलियों (अवधी, ब्रज, हरियाणवी) पर काम कर रहा है। मकसद है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को उनकी स्थानीय बोली–भाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। आईआईटी, रोपड़ ने एआई आधारित ऑटोमैटिक 'मौसम स्टेशन' तैयार किया है। इन्हें हजारों खेतों–गांवों में लगाया जा सकता है। करीब 15,000 रुपए की कीमत वाला यह उपकरण सिंचाई, फसल योजना और कीट–नियंत्रण आदि की सटीक सलाह देगा। बिहार और उप्र में इसका पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। एआई के क्षेत्र में हमने 5 बड़े कदम उठाए हैं, जो निर्णायक साबित हो रहे हैं।

आयातित विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता चिंता की बात

नन्तू बनर्जी

भारत अभी भी चीन और पाकिस्तान जैसे बहुत ज्यादा लड़ाकू पड़ोसियों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा विदेशी आयात पर निर्भर है। स्वदेशीकरण के तथाकथित दबाव के बावजूद, भारत, चीन और पाकिस्तान से दोहरे खतरों का मुकाबला करने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी, जेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी काफी हद तक विदेशी आपूर्तिकताओं पर निर्भर है।

भारतीय रक्षा मंत्रालय की फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की नई मंजूरी से ज्यादा उत्साहित होने की कोई बात नहीं है, जिसकी कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपये (लगभग 40 अरब डॉलर) है, जिसे 'सभी डिफेंस डील्स की सबसे बड़ी डील' कहा जा रहा है। यह बड़ी चिंता की बात है कि देश की आजादी के 78 साल बाद भी, यूक्रेन की तरह भारत को भी अपनी आजादी की रक्षा के लिए आयातित हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता है- फ्रांस से राफेल, संयुक्त राज्य अमेरिका से पोसाइडनजेट, और रूस से एस-400ट्रायम्फ जैसे कई दूसरे हथियार। यहां तक कि उन क्षेत्रों जहां भारत विदेशी सहयोग से रक्षा उपकरण बना रहा है, में भी देश अभी भी विदेशी सबसिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर है।

हालांकि एयरक्राफ्ट और जहाज जैसे प्लेटफॉर्म भारत में असेंबल किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी हाई-एंड कंपोनेंट अभी भी आयातित किए जाते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो जाती है। पिछले कुछ सालों में, भारत ने कई राफेल सौदे किए हैं। इनमें लगभग 7.87 अरब यूरो (लगभग 58,891 करोड़ रुपये) के 36जेट शामिल हैं और हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 26 नेवल वेरिएंट के सौदे हुए हैं, जिसकी कीमत 64,000 करोड़ रुपये है। भारत में बने जेट के साथ क्वालिटी एश्योरेंस के मुद्दों पर कई सालों तक बातचीत चलने के बाद भारत ने 2015 में फ्रांस से 126 राफेल फाइटर खरीदने के समझौते को रद्द कर दिया था।

1950 में, पड़ोसी चीन की अर्थव्यवस्था और रक्षा भारत की तुलना में बहुत कमजोर थी। आज, चीन खुद को अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की सबसे सेल्फ-प्रोपेल्ड घातक मिलिटरी ताकतों में से एक मानता है। भारत के आयात पसंद करने वाले राजनीतिक शासकों की वजह से, देश को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नालॉजी, खासकर जेट इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्डऐरे (एईएसए) रडार, मिसाइल सीकर और स्टील्थ टेक्नालॉजी विकसित करने में बड़ी कमियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास खर्च दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। डीआरडीओ को 2025-26 में कुल रक्षा बजट का सिर्फ 3.94 प्रतिशत मिलेगा।

लंबे खरीद चक्र और आर एंड डी परियोजनाओं में बहुत ज्यादा देरी से आधुनिकीकरण में रुकावट आ रही है। भारत के पास यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए काफी, विश्व स्तरीय परीक्षण अवसंरचना भी नहीं है, जिससे देशी उत्पादनों के विकास और प्रमाणीकरण में कमी आ रही है। भारत के लगभग 80 प्रतिशत रक्षा उपकरण रूस के होने के कारण, रूस देश की रक्षा क्षमताओं का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। रूस तब सामने आया जब पश्चिमी मिलिटरी ताकतों ने भारत को हाई-एंड हथियार आपूर्ति करने से लगभग मना कर दिया था। भारत-रूस रक्षा भागीदारी सिर्फ खरीदार-विक्रेता संबंध से बढ़कर संयुक्त विकास और उत्पादन तक फैली हुई है। भारत में मौजूद बड़े खतरनाक रूसी प्लेटफॉर्म में सुखोई एसयू-30एमकेआई (जो रूस की मदद से भारत में बना), टी-905 'भीष्मइ और टी-22मुख्य लड़ाकू टैंक, ब्रह्मोसक्रूज मिसाइल, रूस में बनी सबमरीन, जिसमें लीज पर लिए गए न्यूक्लियर-पावर्ड जहाज (अकुला-2) और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एमआई-17परिवहन हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

लंबे समय तक, भारत ने अपने निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में आने नहीं दिया, हालांकि वह हथियारों और गोला-बारूद के आयात के लिए विदेशी निजी कंपनियों के साथ सौदा करने में हमेशा खुश था। इत्तेफाक से, डसॉल्ट एविएशन का मालिकाना हक मुख्य रूप से एक फ्रेंच फैमिली होल्डिंग कंपनी, ग्रुप इंडस्ट्रियल मार्सेलडसॉल्ट (जीआईएमडी) के पास है। कंपनी पर परिवार का कड़ा नियंत्रण है, जिसके पास लगभग 67प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। एयरबस के पास लगभग 10प्रतिशत शेयर हैं। भारत में रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2024-25 में कुल उत्पादन का सिर्फ 23प्रतिशत थी, जिसमें ज्यादातर लो-एंड उत्पादन थे। यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स जैसी अत्याधुनिक प्रद्योगिकी के लिए विश्वस्तरीय परीक्षण अवसंरचना की कमी से देशी उत्पादन के विकास और प्रमाणीकरण में देरी होती है।

शुरू में, चीन भी रूसी रक्षा आपूर्ति पर निर्भर था। लेकिन, कम्युनिस्ट शासन ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बहुत प्राथमिकता दी और सालों से रक्षा उत्पादनों की हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया भर में एक बड़ा दावेदार बन गया। चीन का एक लो-टेक हथियार आयातक से एक हाई-एंड देशी डिफेंस मैन्युफैक्चरर और निर्यातक बनना एक लंबे समय की, सरकार की बनाई रणनीति से हुआ है, जिसमें अनुसंधान और विकास में भारी निवेश, इंटेंस मिलिट्री-सिविल फ्यूजन (एमसीएफ), और विदेशी प्रौद्योगिकी का लक्षित प्रदर्शन शामिल है। पिछले दस सालों में, चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनकर उभरा है, जिसके पास स्टील्थ फाइटर्स (जे-20, जे-35), एयरक्राफ्ट कैरियर (फुजियान), और हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्षमता है जो पश्चिमी प्रौद्योगिकी की बेहतरी को चुनौती देते हैं।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) के वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण, निर्यात मात्रा और अतिविकसित सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास के आंकड़े के आधार पर, हाई-एंड डिफेंस इक्विपमेंट (2020-2024) बनाने वाले सर्वोच्च 10 देशों में एयरोस्पेस, नेवल और मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारी निवेश करने वाली बड़ी ताकतें सबसे ज्यादा हैं। ये देश हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इज इल, स्पेन और साउथ कोरिया। हालांकि, भारत अभी भी चीन और पाकिस्तान जैसे बहुत ज्यादा लड़ाकू पड़ोसियों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा विदेशी आयात पर निर्भर है।

स्वदेशीकरण के तथाकथित दबाव के बावजूद, भारत, चीन और पाकिस्तान से दोहरे खतरों का मुकाबला करने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी, जेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी काफी हद तक विदेशी आपूर्तिकताओं पर निर्भर है। यह निर्भरता सीमा विवाद, सीमा पार से आतंकवाद और अस्थिर पड़ोसी के साथ बनी हुई है। जबकि 3,488 किलो मीटर भारत-चीन सीमा (एलएसी) पर तनाव सालों से बना हुआ है, पाकिस्तान से भी सीमा-पार आतंकवाद के लिए लगातार तैयार रहने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हाई-एंड घरेलू रक्षा विनिर्माण में बड़ा निवेश करे।

दैनिक राशिफल

मेष: चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ।

वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कुसंगति व जल्दबाजी से बचें। विवेक से कार्य करें, लाभ होगा।

वृषभ: इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो।

कोर्ट व कचहरी के कार्यों में अनुकूलता रहेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। लाभ होगा।

मिथुन: का, की, कु, घ, ङ:, छ, के, को, हा।

संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। जल्दबाजी न करें।

कर्क: ही, हे, हु, हो, डा, डी, डू, डे, डो।

स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। विवाद न करें।

सिंह: मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे।

मेहनत अधिक होगी। बुरी खबर मिल सकती है। लेन–देन में सावधानी रखें। पुराना रोग उभर सकता है।

कन्या: टो, पा, पी, पू, ष, ण:, ठ, पे, पो।

मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि होगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। घर–बाहर प्रसन्नता रहेगी।

तुला: रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते।

पुराने मित्र व संबंधी मिलेंगे। अच्छे समाचार मिलेंगे। विवाद से बचें। मान बढ़ेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा।

वृश्चिक: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। धनार्जन होगा। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें।

धनु: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

अप्रत्याशित खर्च होंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। वस्तुएं संभालकर रखें।

मकर: भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी।

यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। बकाया वसूली होगी। आय में वृद्धि होगी। प्रसन्नता रहेगी।

कुंभ: गू, गे, गो, सो, सी, सू, स, से, दा।

कार्यस्थल पर सुधार होगा। नए अनुबंध हो सकते हैं। योजना फलीभूत होगी। धनार्जन होगा।

मीन: दी, दू, थ, झ, यं, दे, दो, चा, ची।

पूजा–पाठ में मन लगेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। राजकीय सहयोग मिलेगा। धनार्जन होगा। प्रमाद न करें।

बंगाल का भविष्य: धर्म की लहर या प्रगति की राह?

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, पर राजनीतिक रणभेरी बज चुकी है। इस बार संकेत साफ हैं-चुनाव विकास बनाम विकास के दावे पर नहीं, बल्कि पहचान, अस्मिता और धर्म की ध्वजा के इर्द-गिर्द घूम सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में प्रस्तावित हिंदू सम्मेलनों को भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक उत्सव भर नहीं, बल्कि चुनावी अवसर में बदलने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी यह समझ लिया है कि यदि चुनाव की जमीन धार्मिक विमर्श पर खिसकती है तो उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोलकाता के न्यू टाउन में 'दुर्गा आंगन' का शिलान्यास और उसे बंगाली अस्मिता से जोड़ने का प्रयास इसी रणनीतिक सजगता का हिस्सा है।

बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वर्ग-संघर्ष, वाम वैचारिकी और सामाजिक न्याय के नारों के इर्द-गिर्द घूमती रही। लगभग तीन दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में रहा। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था। किंतु 2011 में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नई धुरी बनी-तृणमूल बनाम भाजपा। आज स्थिति यह है कि वाम और कांग्रेस हाशिए पर हैं और मुकाबला दो ध्रूवों के बीच सिमट चुका है। यही द्विध्रूवीयता चुनाव को अधिक तीखा और अधिक पहचान-केन्द्रित बना रही है। भाजपा का अभियान चार प्रमुख सूत्रों पर टिका है-बंगाल में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेशी घुसपैठ, महिलाओं की असुरक्षा और भ्रष्टाचार। सीमावर्ती जिलों का उदाहरण देकर यह संदेश गढ़ा जा रहा है कि जनसांख्यिकीय संतुलन बदल रहा है। अवैध घुसपैठ का प्रश्न नया नहीं है, पर उसे इस समय राजनीतिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना, शिक्षक भर्ती घोटाले, हिन्दुओं पर बढ़ते अत्याचार एवं भ्रष्टाचार जैसे प्रसंगों को शासन की विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य स्पष्ट है-70 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं में एक साझा असुरक्षा-बोध निर्मित करना, हिन्दुओं को जागृत करना और उसे मतदान व्यवहार में रूपांतरित करना। आज बंगाल में विकास की सबसे बड़ी बाधा घुसपैठियों का बढ़ना है। घुसपैठियों पर विराम लगाना चाहिए न कि इस मुद्दे पर राजनीति हो।

ममता बनर्जी की चुनौती दोहरी है। एक ओर उन्हें यह संदेश देना है कि वे अल्पसंख्यकों की संरक्षक हैं, दूसरी ओर हिंदू मतदाताओं को यह विश्वास भी दिलाना है कि उनकी आस्था और अस्मिता सुरक्षित है। 2021 के चुनाव में जब भाजपा ने 'जय श्रीराम' के नारे को आक्रामक रूप से उछाला, तब ममता ने 'जय मां दुर्गा' और 'चंडी पाठ' के माध्यम से एक सांस्कृतिक प्रत्युत्तर दिया था। इस बार वे दुर्गा आंगन जैसे प्रतीकों के जरिए यह संकेत दे रही हैं कि बंगाली हिंदू पहचान भाजपा की बपौती नहीं है। वे धर्म को राष्ट्रवाद की बजाय क्षेत्रीय अस्मिता के साथ जोड़ती हैं-'बंगाल अपनी संस्कृति से हिंदू है, पर उसकी राजनीति बहुलतावादी है'-यह उनका अंतर्निहित संदेश है। इसी बीच मुर्शिदाबाद में पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर द्वारा 'बाबरी मस्जिद' के शिलान्यास की पहल ने नई जटिलता जोड़ दी है।

इससे मुस्लिम मतदाताओं के भीतर एक अलग ध्रूवीकरण की संभावना पैदा हुई है। यदि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, तो तृणमूल का गणित प्रभावित हो सकती है। 2021 में उसे लगभग 48 प्रतिशत वोट और 223 सीटें मिली थीं-जिसमें मुस्लिम मतों का एकमुश्त समर्थन निर्णायक था। भाजपा 38 प्रतिशत वोट के साथ 65 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष बनी। ऐसे में यदि मुस्लिम मत 5-10 प्रतिशत भी इधर-उधर खिसकते हैं, तो कई सीटों का परिणाम बदल सकता है और भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ सकती है।

यहां प्रश्न केवल गणित का नहीं, राजनीति के चरित्र का भी है। क्या बंगाल का चुनाव धार्मिक पहचान के उभार का प्रयोगशाला बनेगा? या यह प्रयोग अंततः विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के प्रश्नों पर लौटेगा? विडंबना यह है कि जिस बंगाल को कभी देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता था-जहां से उद्योग, शिक्षा और सांस्कृतिक नवजागरण की रोशनी फैलती थी, वह आज अधूरे प्रोजेक्ट्स, धीमी औद्योगिक गति और रोजगार के पलायन से जूझ रहा है।

कोलकाता की सड़कों पर अधूरी मेट्रो लाइनें और बंद कारखानों की चुप्पी विकास की उस कहानी को बयान करती हैं, जो राजनीतिक नारों के शोर में दब जाती है। 2011 में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट का राज्य से बाहर जाना एक प्रतीकात्मक मोड़ था। भूमि अधिग्रहण के प्रश्न पर जनसमर्थन पाने वाली राजनीति ने उद्योग के प्रति संशय का वातावरण भी बनाया। पंद्रह वर्षों बाद भी बंगाल बड़े निवेश की प्रतीक्षा में है। युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, और कई राज्यों में उन्हें 'बांग्लादेशी' कहकर अपमानित किए जाने की खबरें आती हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न भी है। किंतु चुनावी विमर्श में यह पीड़ा गौण हो जाती है, और केंद्र में आ जाता है-धर्म, पहचान और भय।

ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाती हैं; भाजपा राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का।

सी.बी.आई. और ई.डी. की कार्रवाइयों को ममता राजनीतिक प्रतिशोध बताती हैं, जबकि भाजपा उन्हें कानून का पालन। इस टकराव ने प्रशासनिक संवाद को भी राजनीतिक संघर्ष में बदल दिया है। परिणाम यह है कि विकास का एजेंडा आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या धर्म-आधारित ध्रूवीकरण स्थायी राजनीतिक समाधान दे सकता है? इतिहास बताता है कि धार्मिक उभार अल्पकालिक ऊर्जा तो देता है, पर दीर्घकालिक शासन-क्षमता की कसौटी पर उसे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रश्नों से जूझना ही पड़ता है। यदि चुनाव केवल 'कौन किसका प्रतिनिधि है' तक सीमित रह गया, तो 'कौन क्या करेगा' का प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा।

बंगाल की आत्मा बहुलतावाद में रही है-रामकृष्ण परमहंस से लेकर रवींद्रनाथ तक, यह भूमि विविध आस्थाओं और विचारों का संगम रही है। यहां दुर्गा पूजा और मुहर्रम दोनों सामाजिक उत्सव का रूप लेते रहे हैं। यदि राजनीति इस सामाजिक ताने-बाने को चुनावी अंकगणित में बदल देगी, तो समाज की संवेदनशीलता पर चोट पहुंचेगी। दूसरी ओर, यदि धार्मिक प्रतीकों का उपयोग सांस्कृतिक आत्मगौरव के साथ विकास-प्रतिबद्धता को जोड़ने में किया जाए, तो वह सकारात्मक भी हो सकता है। इस चुनाव में भाजपा की रणनीति हिंदू मतों का अधिकतम ध्रूवीकरण है; ममता की रणनीति हिंदू पहचान को बंगाली अस्मिता के साथ समाहित कर अल्पसंख्यकों के विश्वास को बनाए रखना है। मुस्लिम दलों की सक्रियता तृणमूल के लिए चुनौती है, पर वह भाजपा के लिए अवसर भी है। यह त्रिकोणीय-संभावना चुनाव को जटिल बनाती है।

परंतु अंततः लोकतंत्र की परिपक्वता मतदाता तय करता है। यदि बंगाल का मतदाता विकास, रोजगार और सुशासन को प्राथमिकता देता है, तो राजनीतिक दलों को अपना विमर्श बदलना होगा। यदि वह पहचान की राजनीति को स्वीकार करता है, तो वही भविष्य की दिशा बनेगी। प्रश्न केवल यह नहीं कि कौन जीतेगा; प्रश्न यह है कि जीत का एजेंडा क्या होगा?

क्या धर्म के आधार पर लड़ा गया

भारत में कौशल शिक्षा का विस्तार व संभावनाएं

सिकंदर बंसल

भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाला राष्ट्र है। यह स्थिति केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली ऐतिहासिक परिस्थिति है। यदि इस विशाल युवा शक्ति को केवल पारंपरिक डिग्रियों तक सीमित रखा गया तो बेरोजगारी और कौशल-असंतुलन की समस्या गहराएगी। परंतु यदि शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक दक्षताओं, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए तो यही युवा वर्ग भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बना सकता है। पिछले एक दशक में भारत ने कौशल शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना ने तकनीकी कौशल प्रशिक्षण की आधारशिला रखी। समय के साथ यह समझ विकसित हुई कि कौशल शिक्षा को विद्यालय स्तर से ही जोड ा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्पष्ट रूप से कक्षा 6 से 8 तक पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने की अनुशंसा की। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही श्रम, तकनीक और उद्यमिता से परिचित कराना है। आज कई राज्यों में कक्षा 6 से 8 तक बढ़ईगीरी, बागवानी, सिलाई, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत के प्राथमिक कार्य, स्थानीय उद्योगों की जानकारी और उद्यमिता की मूल बातें सिखाई जा रही हैं। यह पहल विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है और शिक्षा को जीवन से जोड़ती है। माध्यमिक स्तर पर समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

यह केंद्र प्रायोजित योजना विद्यालयों में आधारभूत ढांचा विकसित करने, उपकरण उपलब्ध कराने और प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विद्यालयों में कृषि, मोटर वाहन मरम्मत, विद्युत कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा सहयोगी, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा, वस्त्र निर्माण, खुदरा व्यापार, सौंदर्य एवं कल्याण, निर्माण कार्य, बैंकिंग सेवा सहयोगी, दूरसंचार सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई विद्यालयों में खेल एवं फिटनेस से जुड़े पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हुए हैं। इन कार्यक्रमों को मानकीकृत और स्तरबद्ध रूप देने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा लागू की गई है। यह रूपरेखा कौशल शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है और प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित ज्ञान और दक्षता निर्धारित

करती है। इससे विद्यालय स्तर से प्राप्त योग्यता आगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च प्रशिक्षण केंद्रों में मान्य होती है। यह व्यवस्था शिक्षा और रोजगार के बीच सेतु का कार्य करती है। भारत में कई सफल कार्यक्रम कौशल शिक्षा को गति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण और प्रमाणन दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उद्योगों में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर रही है, जिससे युवाओं को वास्तविक कार्यस्थल अनुभव मिलता है। जन शिक्षण संस्थान योजना ग्रामीण और वंचित वर्गों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दे रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ने ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा है। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कौशल विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है। अनेक प्रशिक्षित युवाओं ने लघु उद्यम स्थापित किए हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित किया है। यह परिवर्तन दशार्ता है कि कौशल आधारित शिक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विद्यालयी व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ राज्य विशेष रूप से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। गुजरात को माध्यमिक स्तर के बड़ी संख्या में विद्यालयों में व्यावसायिक विषय संचालित करने के कारण अग्रणी माना जाता है। केरल ने अपने व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मॉडल के माध्यम से कौशल शिक्षा को सुव्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण स्वरूप दिया है। हरियाणा ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के अनुरूप विद्यालयी पाठ्यक्रमों को व्यापक रूप से लागू किया है। पश्चिम बंगाल ने राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य सेवा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। ये उदाहरण दशार्ते हैं कि विभिन्न राज्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कौशल शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं और समग्र शिक्षा योजना के सहयोग से विद्यालय स्तर पर इसका दायरा बढ़ा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी इस दिशा में प्रेरक हैं। दक्षिण कोरिया ने औद्योगिक विकास के साथ तकनीकी शिक्षा को जोड़ा और विश्वस्तरीय विनिर्माण क्षमता विकसित की। जापान ने तकनीकी महाविद्यालयों और उद्योगों के सहयोग से अपनी उत्पादन शक्ति को मजबूत किया। चीन ने व्यापक स्तर पर व्यावसायिक विद्यालयों का विस्तार कर उत्पादन आधारित प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी। अमेरिका में सामुदायिक महाविद्यालय युवाओं को दो वर्षीय व्यावहारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगारोन्मुख बनाते हैं। उत्तर कोरिया में भी राज्य नियंत्रित तकनीकी प्रशिक्षण उत्पादन प्रणाली से जुड़ा है। इन देशों का अनुभव दशार्ता है कि कौशल शिक्षा केवल शैक्षिक सुधार नहीं, बल्कि आर्थिक रणनीति का हिस्सा है।भारत ने भी स्पष्ट रूप से यह संकल्प लिया है कि उसकी युवा शक्ति केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि दक्ष और आत्मनिर्भर होगी। वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में शिक्षा और कौशल विकास के लिए उल्लेखनीय प्रावधान किए गए हैं।

समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से विद्यालयी व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है, जबकि अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण और शिक्षुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी, उपकरणों की अपर्याप्त उपलब्धता और समाज में पारंपरिक डिग्री को अधिक महत्व देने की मानसिकता बाधा बनती है। उद्योगों और विद्यालयों के बीच समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के साथ रोजगार का स्पष्ट मार्ग दिखाई दे, तो व्यावसायिक शिक्षा अधिक आकर्षक बनेगी। कौशल शिक्षा विकल्प नहीं, बल्कि आर्थिक भविष्य की आधारशिला है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक पुरुषोत्तम पाण्डेय द्वारा मौनेक्स ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, बी-12, निकट एमएमजी अस्पताल, शंभू दयाल काम्पलेक्स, जीटी रोड, गाजियाबाद से मुद्रित एवं 498 प्रथम तल, मैत्री लेन, सैक्टर-5, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित।

सम्पादक : विजय प्रकाश पाठक
Mob : 9910460742
website : www.swastiksahara.com
E-mail : swastiksaharanews@gmail.com

विधि सलाहकार
टेट्रा लीगल एलएलपी, लॉ फर्म, नई दिल्ली
मोबाइल नंबर - +91 99990 74369

City Office:
11, Maliwara, Near Pyarelal Park, Vasant Road, Ghaziabad-201001Phone : 0120-4252839

सेहत/स्वास्थ्य

आपकी त्वचा दे रही है 5 गंभीर बीमारियों का चेतावनी, इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

अगर पाचन खराब रहने लगे, वजन कम होने लगे, भूक कम लगे या अचानक से अधिक कमजोरी महसूस होने लगे, तो यह इस बात का संकेत होता है कि शरीर में किसी न किसी गडबड़ी की शुरूआत हो चुकी है।

जब भी हमारे में शरीर में किसी गड़बड़ी की शुरूआत होती है, तो इसके लक्षण धीरे-धीरे नजर आते हैं। लेकिन जब हम इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो शरीर में पनप रही यह गड़बड़ी धीरे-धीरे गंभीर बीमारी में बदल जाती हैं। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। अगर पाचन खराब रहने लगे, वजन कम होने लगे, भूक कम लगे या अचानक से अधिक कमजोरी महसूस होने लगे, तो यह इस बात का संकेत होता है कि शरीर में किसी न किसी गड़बड़ी की शुरूआत हो चुकी है।

हमारी आंखों और स्किन पर भी बीमारी के संकेत नजर आता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्किन किस तरह बताती है कि हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी पनप रही है।

स्किन के इशारे समझें

अगर आपके बालों के बीच की रेखा भी पतली हो रही है और बाल लगातार झड़ रहे हैं। तो यह हार्मोनल इंबैलेंस का एक संकेत हो सकता है। ऐसा डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की वजह से हो सकता है।

अगर आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं और यह बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि आंखों के नीचे काले घेरे सिर्फ नींद न पूरी होने की वजह से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा शरीर में आयरन की कमी से हो सकता है।

अगर आपकी आईब्रो के बाल पतले होते जा रहे हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। थायराइड हार्मोन के इंबैलेंस की वजह से ऐसा हो सकता है।

अगर आपकी आंखों के आसपास पीले पैच हो रहे हैं। तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से होता है। ऐसे में आपको एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए।

शरीर में एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने की वजह से गालों पर पिग्मेंटेशन या झाइयां हो सकती हैं। महिलाओं के चेहरे पर अनचाहे बाल भी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस की ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर में टेस्टेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है।

त्वचा में क्रैक या हल्की दरारें नदजर आना इस ओर इशारा करता है कि आपके शरीर में विटामिन बी12 का लेवल काफी कम है। वहीं त्वचा में रूखापन ओमेगा 3 की कमी का संकेत है। फेस पर एक्ने होना जिंक की कमी का संकेत होता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में जिंक से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए।

ब्यूटी / फैशन

सर्दियों में रूखी त्वचा से हैं परेशान, ये नेचुरल फेस पैक देगा इंस्टेंट ग्लो

सर्दियों में थोडी सी केयर फेस की रौनक को वापस ला सकती है। इसके लिए घर में फेस पैक तैयार करके लगा सकती हैं। वहीं सप्ताह में दो बार यह फेस पैक लगाने से आपका चेहरा चांद जैसा खिला-खिला नजर आएगा। आज हम आपको इस फेस पैक के बारे में बताने जा रहे हैं।

सर्दियों के मौसम में स्किन का रूखापन बढ़ जाता है और ठंडी हवाएं स्किन को बेजान बना देती हैं। कई बार ड्राईनेस इतनी ज्यादा होने लगती है कि कई बार दिन में दो बार कोल्ड क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है। फेस की रौनक कहीं खो जाती है। इससे चेहरा रूखा और बेजान दिखने लगता है। इस मौसम में थोड़ी सी केयर फेस की रौनक को वापस ला सकती है। इसके लिए घर में फेस पैक तैयार करके लगा सकती हैं। वहीं सप्ताह में दो बार यह फेस पैक लगाने से आपका चेहरा चांद जैसा खिला-खिला नजर आएगा। क्योंकि यह पूरी तरह से नेचुरल फेस पैक है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस फेस पैक के बारे में बताने जा रहे हैं।

केले और मलाई का फेस पैक

फेस की खोई रौनक वापस पाने के लिए आप केले और मलाई का फेस पैक सबसे अच्छा ऑप्शन है। स्किन के लिए मलाई फायदेमंद होती है। जिन लोगों की त्वचा ड्राई होती है, उनको नियमित रूप से फेस पर मलाई लगानी चाहिए।

केला में विटामिन ए, बी और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह सभी पोषक तत्व स्किन को पोषण देने का काम करते हैं। केले के फेस पैक को चेहरे पर लगाने से झुर्रियां जल्दी नहीं आती हैं।

ऐसे बनाएं फेस पैक

आधा पका केला
आधा चम्मच शहद
एक चम्मच मलाई

ऐसे बनाएं फेसपैक

सबसे पहले आधा पका केला लें। इसको चम्मच से अच्छे से मैश कर लें। फिर मलाई और शहद डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसको तब तक मिलाना है, जब तक यह क्रीमी न दिखने लगे। इसको फेस पर अप्लाई करें और 15 मिनट तक सूखने लगे। फिर फेस को गुनगुने पानी से धो लें। इसके बाद लाइट मॉइस्चराइजर अप्लाई करें।

जानिए कब लगाएं

सप्ताह में दो बार यह फेस पैक लगाया जा सकता है। इसके लिए रात को सोने से पहले फेस को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद फेस पैक लगाएं। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए सोने से पहले लगाना बेहतर है।

बेसन-हल्दी फेस पैक

बेसन - 2 चम्मच
हल्दी पाउडर- 1 चम्मच
दही या गुलाबजल - 1 चम्मच
शहद - 1 चम्मच

ऐसे बनाएं फेस पैक

इस फेस पैक को बनाने के लिए बेसन और हल्दी पाउडर को मिला लें। फिर इसमें दही या गुलाब जल मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो इसमें शहद मिला सकते हैं। फिर इस मिश्रण को फेस पर 15-20 मिनट के लिए अप्लाई करें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। आप सप्ताह में दो बार इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकती हैं।

पर्यटन

गोवा से केरल तक, ये हैं भारत के 5 सबसे रोमांटिक बीच, यादगार बन जाएगा वेकेशन

भारत में कई ऐसी बीच है, जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। यहां की शाम को उनके खास पलों को यादगार बना सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे बीचेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप जा सकते हैं।

नई-नई जगह एक्सप्लोर करने वाले लोगों के लिए घूमना एक थेरेपी है। नई जगहों पर जाने के बाद व्यक्ति रिफ्रेश महसूस करता है। अक्सर कपल्स ऐसी डेस्टिनेशन की तलाश करते हैं, जहां पर उनका रिश्ता ताजगी से भर जाए और वह जगह उनको रोमांटिक लगे। भारत में कई ऐसी बीच है, जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। यहां की शाम को उनके खास पलों को यादगार बना सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे बीचेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप जा सकते हैं।

पालोलेम बीच

बता दें कि गोवा एक ऐसा बीच है, जो हर किसी को एनर्जी से भर देता है। गोवा का माहौल एकदम अलग है। यह जगह जितनी खूबसूरत है, उतने ही यहां के बीच भी रोमांटिक हैं। ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां के पालोलेम बीच पर जाएं। यहां पर आपको समसेट और सनराइज जरूर देखना चाहिए।

मरारी बीच

कपल्स को वही जगह पसंद आती है, जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ न हो। ऐसा ही केरल का मरारी बीच है, जहां पर बेहद शांति है। सनसेट के समय अपने पार्टनर के साथ यहां हाथों में हाथ डाले नंगे पांव वॉक कर सकते हैं। शाम के समय यहां का आसमान और चारों ओर फैले नारियल के पेड़ किसी कैनवास पर उकेरी गई पेंटिंग से कम नहीं लगता है।

कन्याकुमारी बीच

तमिलनाडु की कन्याकुमारी बीच बेहद खास है। यह बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन इस जगह को खास बनाता है। शाम को सूरज ढलने के समय आसमान के साथ समुद्र का पानी भी पीला, नारंगी और लाल रंग का दिखता है। ठंडी हवाओं के बीच समुद्र का किनारा आपको रोमांटिक एहसास कराता है।

हाफ मून बीच

चांद का रोमांस से जोड़ा गया है। ऐसे में अगर अपने पार्टनर को स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं, तो कर्नाटक के गोकर्ण में हाफ मून बीच पर जाएं। हाफ मून बीच आधे चांद के आकार का है। शाम को सूरज की किरणें रेत पर पड़ते ही चमक जाता है। यह शांत बीच है और यहां पर हट भी बने हुए हैं। जहां पर आप पार्टनर के साथ सुकून से बैठकर सनसेट का नजारा देख सकते हैं।

कोवलम बीच

केरल का कोवलम बीच कपल्स को अपना दीवाना बना सकता है। बता दें कि इस बीच की अलग ही वाइब्स है। इस बीच पर एक लाइट हाउस भी है, जहां से शाम को आप दूर तक फैला समुद्र और सनसेट को निहार सकते हैं। अगर आपको वॉटर स्पोर्ट्स पसंद है, तो कपल इस एक्टिविटी का भी लुत्फ ले सकते हैं। सनसेट इस जगहको बेहद खूबसूरत बना देता है। आप यहां पर वॉक के साथ कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं।

घरेलू नुस्खे

विंटर जैकेट की कर रहे हैं पैकिंग? 99% लोग करते हैं ये गलती, अगली सर्दी तक लग जाएगी फंगस

सर्दियों के कपड़े, खासकर जैकेट को स्टोर करते समय कुछ आम गलतियां जैसे गीला रखना या प्लास्टिक बैग में पैक करना, कपड़ों में फंगस और बदबू का कारण बन सकती हैं। जानिए अपनी महंगी जैकेट को अगले सीजन के लिए सुरक्षित रखने का सही तरीका ताकि वे खराब न हों।

फरवरी का महीने में अब धीरे-धीरे ठंड अपने समाप्ति पर आ चुकी है। मौसम अब दिन में गर्म होने लगा है। जैसी है गर्मी बढ़ेगी, वैसे ही घरों में सर्दियों के कपड़े धोकर रखने का काम शुरू हो जाएगा। सर्दियों के कपड़ो को धोना तो काफी आसान है, लेकिन इसको स्टोर करना काफी मुश्किल है। हालांकि, कुछ आम गलतियां, जिन्हें हम सभी कर देते हैं। जरा-सी भी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। जब अगले सर्दी के सीजन में जैकेट निकाली जाती है, तो उसमें दाग, रंग फीका पड़ना या कपड़ों से अजीब सी बदबू आने लगती है। आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कपड़े स्टोर करने का सही तरीका।

एक बार पहनी हुई जैकेट स्टोर करना

अक्सर लोग जैकेट धोकर अच्छे से सुखा तो लेते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें कभी पहनना पड़ जाए, तो वह एक बार पहनकर उसे स्टोर करने लग जाते हैं। ऐसे में लगता है कि एक बार ही तो पहना है, क्या ही होगा। फिर भी पसीना, धूल और बॉडी ऑयल कपड़े में रह जाते हैं, जो बाद में बदबू और बैक्टीरिया का कारण बन जाता है। इसलिए इसको एक बार ही क्यों न पहना हो, फिर भी दोबारा से जैकेट को धोकर ही रखे। इसलिए जैकेट को सही से साफ तरीके से रखे।

एक बार पहनी हुई जैकेट स्टोर करना

अक्सर लोगों से गलती हो जाती है कि जैकेट को अच्छे से सुखाते नहीं है। जैकेट ऊपर से तेज धूप में सुखाने के बाद उसे उल्टा नहीं करते। यदि जैकेट को आप सीधा-उल्टा करके सुखाएं, तो इसकी नमी से अच्छे से सूख जाएगी। पफर या फिर मोटी जैकेट के अंदर की लेयर को पूरी तरह सुखाना बेहद जरुरी है। यदि इसमें नमी रहेगी और ऐसे ही स्टोर करेंगे, तो यह अगली सर्दी में पहनने के लायक नहीं रहेगी।

प्लास्टिक बैग में पैक करना

कई लोग जैकेट को सुखाने के बाद प्लास्टिक बैग में रख देते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। प्लास्टिक कवर में हवा का आवागमन नहीं होता, जिससे अंदर नमी जमा हो सकती है। यही नमी बदबू और फंगस पैदा करती है, जो जैकेट को खराब कर सकती है। इसलिए जैकेट को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक की बजाय कॉटन या कपड़े के बैग का उपयोग करना बेहतर होता है। यह तरीका जैकेट को लंबे समय तक सही स्थिति में रखने में मदद करता है।

सही से कपड़े को स्टोर न करना

अक्सर लोग अलमारी में गर्मी वाले कपड़े होते हैं, उसी में जैकेट भी रख देते हैं। ऐसे में रोज-रोज वह कपड़े को हाथ लगाते है, जिससे जैकेट अगली सर्दी तक और मिट्टी व बार-बार हाथ लगने की वजह से गंदे होने लगते हैं। इसलिए, आप चाहे तो अगले साल सर्दी शुरू होने पर जैकेट बिना धोए पहनने को मौका मिले, तो इसको सही से स्टोर करें।

सीएम योगी के 'टेंपल इकॉनमी मॉडल' से मजबूत हो रही यूपी की अर्थव्यवस्था

पिछली सरकारों में उपेक्षित रहे राज्य के प्राचीन धार्मिक स्थलों पर आधारभूत ढांचे के विकास से मिला पर्यटन को बल

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक पर्यटन केवल आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'टेंपल इकॉनमी मॉडल' ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्राचीन धार्मिक स्थलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए तो आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था, तीनों को एक साथ मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछली सरकारों के दौर में उपेक्षित रहे अनेक धार्मिक स्थलों पर अब सुनियोजित विकास कार्यों ने तस्वीर बदल दी है। सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण, आधुनिक यात्री सुविधाएं, समुचित पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, ठोस सुरक्षा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था जैसे बुनियादी सुधारों ने श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाया है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्ष उत्तर प्रदेश में 122 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। यह संख्या न केवल राज्य के प्रशासनिक प्रबंधन की क्षमता को दशार्ती है, बल्कि इस तथ्य को भी स्थापित करती है कि धार्मिक पर्यटन अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन चुका है।

बड़े धार्मिक केंद्रों से लेकर छोटे शहरों तक असर

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर के विकास और भव्य अवसंरचना निर्माण ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। वहीं वाराणसी में काशी क्षेत्र के व्यापक विकास, घाटों के पुनरुद्धार और यात्री सुविधाओं के विस्तार ने पर्यटन को नई ऊंचाई दी। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के विकास और महाकुंभ व माघ मेला जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों के सफल संचालन ने भी इस मॉडल की प्रभावशीलता को प्रमाणित किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 'टेंपल इकॉनमी मॉडल' का प्रभाव केवल इन प्रमुख धार्मिक शहरों तक सीमित नहीं रहा। मथुरा, चित्रकूट, नैमिषारण्य, विंध्याचल और अन्य छोटे धार्मिक नगरों में भी आधारभूत ढांचे के विकास के साथ स्थानीय व्यापार और सेवाक्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिला नया जीवन

इसी तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थलों में भी सुविधाएं बढ़ने से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई और इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, प्रसाद उद्योग, होटल एवं गेस्ट हाउस व्यवसाय, परिवहन सेवाओं, रेस्तरां, गाइड सेवाओं और छोटे व्यापारियों के कारोबार में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ। हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिले। हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की मांग बढ़ने से 'लोकल टू ग्लोबल' की अवधारणा को भी बल मिला है। धार्मिक पर्यटन स्थलों पर स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री बढ़ी है, जिससे ग्रामीण और अर्धशहरी अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचा है।

सनातन अर्थशास्त्र का आधुनिक मॉडल

अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल का कहना है कि 122 करोड़ पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आगमन यह दशार्ता है कि धार्मिक-सांस्कृतिक केंद्र अब 'इमोशनल स्पेस' से आगे बढ़कर 'इकोनॉमिक जोन' बन चुके हैं। योगी सरकार ने भारत की पारंपरिक ग्राम-नगर-तीर्थ संरचना को आधुनिक नीति और अवसंरचना से जोड़कर एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें आस्था आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनती है। प्रदेश सरकार के हालिया बजट में नगर विकास के लिए ₹26,514 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह निवेश केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि नगर-आधारित आर्थिक पुनरुत्थान की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र के प्रस्तावित विकास जैसे कदम सांस्कृतिक भूगोल को आर्थिक भूगोल में रूपांतरित करने की दिशा में उठाए गए हैं। रामपथ, तीर्थ सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक केंद्रों और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार धार्मिक स्थलों को स्थायी आर्थिक केंद्रों में बदलने का आधार तैयार कर रहा है।

धार्मिक पहचान से आर्थिक पुनर्जागरण तक

आईआईएम लखनऊ की अयोध्या पर आधारित हालिया रिपोर्ट भी टेंपल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। रिपोर्ट में अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आर्थिक गतिविधियों में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन ने आतिथ्य, परिवहन, निर्माण और सेवा क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा कीं। 150 से अधिक नए होटल और होमस्टे स्थापित हुए, हजारों एमएसएमई सक्रिय हुए और स्थानीय बाजारों में कारोबार कई गुना बढ़ा। छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। रियल एस्टेट क्षेत्र में भी तेज उछाल देखा गया, जिससे निजी निवेश को मजबूती मिली। अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे, आधुनिक रेलवे स्टेशन, चौड़ी सड़कों और नगर सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों ने अयोध्या को एक सुव्यवस्थित धार्मिक-पर्यटन केंद्र में परिवर्तित करने की दिशा में ठोस आधार प्रदान किया।

आस्था से अर्थव्यवस्था तक का समन्वय

योगी सरकार का यह मॉडल इस सोच पर आधारित है कि आस्था और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यदि धार्मिक स्थलों का समग्र विकास किया जाए, तो यह न केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का माध्यम बनता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और निवेश आकर्षण का भी आधार तैयार करता है। आज उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, परिवहन नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं में भी तेजी देखी जा रही है। बेहतर कानून-व्यवस्था और सुव्यवस्थित आयोजन क्षमता ने निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाया है।

पांडुलिपियों, दुर्लभ ग्रंथों को सहेजकर डिजिटल रूप देगी योगी सरकार

विरासत के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा ज्ञान भारतम मिशन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

गोरखपुर। वर्तमान और भावी पीढ़ियां विरासत पर गर्व की अनुभूति कर सकें, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने हमेशा प्रतिबद्धता जताई है। इसी क्रम में भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित करने के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अभियान 'ज्ञान भारतम मिशन' में प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। पांडुलिपियों और दुर्लभ ग्रंथों को सहेजकर विश्व पटल पर डिजिटल रूप देने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में जिला स्तर पर पांडुलिपियों को चिन्हित व संग्रहीत करने के आदेश जारी किए हैं। इसके पर्यवेक्षण के लिए हर जिले में वहां के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

विरासत के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे 'ज्ञान भारतम मिशन' के अंतर्गत हर जिले में उपलब्ध भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पांडुलिपियों एवं दुर्लभ ग्रंथों का वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण किया जा रहा है ताकि यह धरोहर शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए सुलभ हो सके। उत्तर प्रदेश के लिए यह अभियान और भी विशेष है क्योंकि उत्तर प्रदेश को प्राचीन ज्ञान दर्शन, साहित्य और संस्कृति की भूमि माना जाता है।

गोरखपुर के उप निदेशक संस्कृति यशवंत सिंह राठौर ने बताया कि 'ज्ञान भारतम मिशन' के अंतर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, मठों, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों, व्यक्तियों के पास उपलब्ध पांडुलिपियों, हस्तलिखित ग्रंथों, ताड़पत्रों, भोजपत्रों और अन्य दस्तावेजों की पहचान, सर्वेक्षण, कैटलॉगिंग, संरक्षण तथा डिजिटलीकरण का कार्य किया जाना है। पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण होने से यह ज्ञान भारतम पोर्टल के माध्यम से आमजन को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।

रखरखाव के अभाव में व्यक्तियों या संस्थाओं के पास उपलब्ध कई ग्रंथ नष्ट होने की कगार पर हैं। अब जिला स्तर पर इन ग्रंथों को चिन्हित करने और उनके संरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला स्तर पर अभियान चलाकर पांडुलिपियों का संग्रह करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से संपर्क कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें हाथ से लिखे उन ग्रंथों को शामिल किया जाएगा जो 75 वर्ष से अधिक प्राचीन हों। जिला स्तर पर तैयार सूची संस्कृति विभाग के जरिये प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार को प्रेषित की जाएगी। जहां उच्च गुणवत्ता की स्कैनिंग के बाद इसका डिजिटल रूप तैयार हो जाएगा। इस मिशन की विशेषता यह है कि इसमें पांडुलिपियां संबंधित संग्रहकर्ता संस्था या व्यक्ति के ही अधिकार में रहेंगी।

प्यास की राजनीति से उबरा बुंदेलखंड: 98 प्रतिशत से अधिक घरों तक नल से जल

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। कभी पानी की किल्लत और प्यास की राजनीति के लिए चर्चित रहा बुंदेलखंड अब नल से जल आपूर्ति के मामले में नई पहचान बना रहा है। 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बुंदेलखंड मंडल के सातों जिलों में 98 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण घरों को फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराया जा चुका है। कई जिलों में यह कवरेज 99 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार इसे ग्रामीण जीवन स्तर में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत मान रही है।

बांदा में कुल 2,68,960 ग्रामीण घरों में से 2,68,722 घरों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है, जो लगभग 99.91 प्रतिशत है। चित्रकूट में 1,63,970 में से 1,63,698 घरों तक कनेक्शन पहुंचा है, जो 99.83 प्रतिशत है। महोबा में 1,40,149 में से 1,39,904 घरों (99.83 प्रतिशत), हमीरपुर में 1,86,530 में से 1,85,693 घरों (99.55 प्रतिशत) और ललितपुर में 2,06,983 में से 2,05,966 घरों (99.51 प्रतिशत) को नल से जल सुविधा मिल चुकी है। झांसी में 2,51,232 में से 2,49,111 (99.16 प्रतिशत) तथा जालौन में 2,12,069 में से 2,08,174 घरों (98.16 प्रतिशत) को कवर किया गया है। समूचे बुंदेलखंड जोन में कुल

7,59,609 घरों में से 7,58,017 घरों तक कनेक्शन पहुंच चुका है, जो 99.79 प्रतिशत कवरेज दशार्ता है।

2019 से पहले प्रदेश में ग्रामीण नल जल कवरेज दो प्रतिशत से भी कम था। बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र में पाइप से पेयजल सुविधा अपवाद मानी जाती थी। जल जीवन मिशन की शुरूआत के बाद बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का निर्माण किया गया। ट्यूबवेल, पंप हाउस, ओवरहेड टैंक और व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का कार्य तेजी से पूरा किया गया। भौतिक संरचना लगभग पूर्ण हो चुकी है और अब ध्यान कमीशनिंग तथा नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है।

इससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। दूरदराज क्षेत्रों में पानी लाने की मजबूरी खत्म होने से समय की बचत, स्वास्थ्य में सुधार और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक शत प्रतिशत कनेक्शन और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

पत्रकार एसोसिएशन का होली मिलन समारोह 22 फरवरी को : अजय जैन

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। पत्रकार एसोसिएशन गाजियाबाद की एक बैठक एसएसडी जैन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित की गई। जिसमें होली मिलन समारोह के साथ-साथ अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में भारी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय जैन की अनुमति से महामंत्री संजीव वर्मा ने सभा की कार्यवाही शुरू की।सभी के विचार विमर्श के बाद अजय जैन ने प्रस्ताव रखा कि 22 फरवरी को होली मिलन समारोह आयोजित किया जाए क्योंकि देर होने पर सभी पत्रकारबंधु अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए इधर-उधर जाते हैं इसलिए 22 फरवरी को होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसका सभी उपस्थित पत्रकारों ने अनुमोदन किया।

यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष अजय जैन ने दी। रश्मि ओझा ने प्रस्ताव रखा कि सभी सदस्यों की सहमति से प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया जाता है और इस वर्ष भी होली का आयोजन धूमधाम से मनाया जाएगाउन्होंने प्रस्ताव रखा कि होली मिलन समारोह के संबंध में सभी सदस्यों व पदाधिकारी की ड्यूटी चिन्हित कर दी जाए।

जिससे वह अपना-अपना कार्य ठीक से सम्पन्न कर सकें। संजीव वर्मा,किशन सिंह,मनीष गुप्ता,कुलदीप त्यागी आदि ने प्रस्ताव रखा कि हम सभी को मिल-जुलकर काम करना चाहिए। हम लोग जिस प्रकार से भविष्य में पत्रकारों की सहायता करते रहते हैं इस तरह के कार्य भी होते रहने चाहिए। इस सापेक्ष में सी पी सिंह,मीनाक्षी शर्मा,सविता शर्मा आदि ने कहा कि हमें पहले अपनी संस्था के जो सम्मानित सदस्य हैं उनकी सहायता करनी चाहिए जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में सकारात्मक विचार वाले पत्रकारों को सदस्य बनाना चाहिए। जिसका सभी ने अनुमोदन किया। उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी ने कहा हमारी संस्था बहुत पुरानी हो चुकी हे और रजिस्टर्ड भी है। भविष्य में इस बैनर तले जनहित में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा।

अध्यक्ष अजय जैन ने इस पर कहा कि पत्रकार एसोसिएशन ने भविष्य में अनेकों कार्यक्रम किए जैसे हेल्थ कैम्प लगवाना, फास्ट टैग कैम्प, आधार कार्ड बनवाना, गरीबों को कंबल और कपड़े वितरित करना, कई पत्रकारों की आर्थिक सहायता करना एवं पत्रकारों पर गलत तरीके से किसी ने कोई कार्रवाई की है तो उसका पुरजोर विरोध करना आदि-आदि अनेकों जनहित के कार्य करती रहती है।

आप लोगों की सहमति से भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य के अलावा संस्था आप सबके सहयोग से करती रहेगी। महामंत्री संजीव शर्मा ने कहा कि अन्य सूचनायें व्हाटसप पर सभी को जल्द मिलती रहेंगी।

इस अवसर पर मुख्य रूप से अध्यक्ष अजय जैन, महामंत्री संजीव वर्मा, कोषाध्यक्ष योगेश कौशिक, उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी,सचिव रश्मि ओझा,सह सचिव किशन सिंह,सह सचिव मनीष गुप्ता,संरक्षक सुनील त्रिपाठी,मीडिया प्रभारी रिंकू नारायण,वरिष्ठ सदस्य मीनाक्षी शर्मा,राहुल शर्मा,श्रीराम, सविता शर्मा,सुधीर रस्तोगी,नरेश कुमार,रवि तुषार, सी पी सिंह,शिवम(पप्पू),समेत भारी संख्या में पत्रकारबंधु उपस्थित थे।

किसानों को बनाया यूपी की समृद्धि का भागीदार

शहर व गांव के बीच अंतर घटा रही योगी सरकार, पलायन पर भी प्रभावी रोक

बजट में खास ध्यान, कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपये

2017 में सत्ता संभालने के तत्काल बाद योगी सरकार द्वारा किसानों की 36 हजार करोड़ रुपये कर्जमाफी से लेकर केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के 94,668.58 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने तक, डबल इंजन सरकार ने किसानों को आर्थिक समृद्धि के केंद्र में रखा है। डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ अकाउंट में देकर बिचौलियों का राज समाप्त किया गया। बजट 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट कर देती है। यह राशि पिछले बजट के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने यूपीएग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के तहत विश्वस्तरीय हैचरी तथा विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बा' सहायतित परियोजना के लिये 155 करोड़ रुपये, एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिये 245 करोड़ रुपये तथा किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवाल्विंग फण्ड योजना के लिये 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर में परिवर्तित करने की योजना के लिए 673.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ये बजट प्रावधान कृषि एवं सबद्ध क्षेत्रों के तकनीकी उन्नयन में मददगार होंगे।

विशेषज्ञ की राय

'योगी सरकार ने गांव व किसान को समृद्धि का आधार कहा था। सरकार ने पौने नौ साल में इसे वास्तविकता के धरातल पर उतारा भी है। चाहें बजट प्रावधान हों या किसान पाठशाला के जरिये खेती-किसानी को उन्नत तकनीक से जोड़ना, सरकार किसानों को आत्मनिर्भरता व उद्यमिता की तरफ ले जा रही है। किसी भी प्रदेश के समावेशी विकास के लिए जरूरी है कि कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोग सिर्फ सरकारी अनुदान योजनाओं पर आश्रित न रहें। राज्य की अर्थव्यवस्था व समृद्धि में उनकी अन्य क्षेत्रों के समान ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। इससे शहर व गांवों के बीच की खाई पटती है और पलायन पर रोक लगती है। योगी सरकार इस दिशा में लगातार प्रभावी काम कर रही है।'

रविंद्र कुमार सिंह, किसान नेता आजमगढ़

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव व अन्नदाता किसान सशक्त होंगे तो देश समृद्ध रहेगा और उत्तर प्रदेश के समावेशी विकास का लक्ष्य भी तभी प्राप्त होगा। इसी नीति को केंद्र में रखते हुए योगी सरकार ने गांव और किसान को अपनी प्राथमिकता में रखकर बीते 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण किया है। यह नया उत्तर प्रदेश शहर व गांव के बीच अंतर को पाटता है, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकता है। इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार का बजट 2026-27 भी खेती-किसानी और ग्राम्य विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाता दिखाई दे रहा है। यह ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देता है। किसानों को नई तकनीकों से, नए बाजारों से जोड़ता और उद्यमिता से जोड़ता है। खेती-किसानी व इससे संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के नए माध्यमों को जन्म देता है। यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दी जा रही मजबूती

बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बार फिर मजबूती दी गई है। प्रदेश के सभी जनपदों को शामिल करते हुए 94,300 हेक्टेयर में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग योजना संचालित है। बजट में इसके लिए 298 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निजी नलकूपों को अनवरत बिजली आपूर्ति हो, इसका ध्यान रखा गया है। इसके लिए 2400 करोड़ प्रस्तावित हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए लगभग 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार किसानों के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम पर लगातार कार्यरत है।

ग्रामीण अर्थतंत्र में नई ऊर्जा भरेगा गन्ना

पिछली सरकारों की अनदेखी के शिकार गन्ना किसानों के जीवन में 2017 के बाद से मिठास घुल गई है। योगी सरकार ने 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया। इस ऐतिहासिक निर्णय ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की। अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य 400 रुपये प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। इस वृद्धि से गन्ना किसानों को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा। योगी सरकार के कार्यकाल में यह चौथी बार है, जब गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई। यह निर्णय गन्ना किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण अर्थतंत्र में भी नई ऊर्जा भरेगा।

दुग्ध, मत्स्य पालकों के लिए भी खोले दरवाजे

योगी सरकार ने दुग्ध व मत्स्य पालकों के लिए भी दरवाजे खोले हैं। सहकारी क्षेत्र के तहत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मथुरा में पहले 30 हजार लीटर क्षमता की नवीन डेयरी परियोजना प्रस्तावित की गयी थी, लेकिन अब 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है। सरकार ने दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण व उन्हें पुनर्जीवित करने की योजना पर भी जोर दिया है। छुट्टा गोवंश के कारण किसानों को होने वाली समस्याओं के निदान पर भी सरकार ने जोर लगाया। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया है। मत्स्य पालक किसानों का भी बजट में ख्याल रखा गया है। इसके अतिरिक्त 36.87 लाख किसानों को निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट, लगभग 83 हजार सोलर पंप की स्थापना, लगभग 32 हजार खेत तालाबों का निर्माण, 2.46 लाख से अधिक कृषि यंत्रों का वितरण और किसान पाठशाला में लगभग दो करोड़ किसानों की सहभागिता से भी अन्नदाता किसानों के जीवन में बदलाव लाया गया है।

योगी सरकार का किसानों की 'आर्थिक समृद्धि' पर विशेष जोर

धान खरीद अभियान के जरिए योगी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य अन्नदाता किसानों की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना है। एक ओर सरकार धान की निर्बाध खरीद कर रही है, तो दूसरी ओर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किसानों को सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई और किसानों को समय पर पैसा मिल रहा है। धान खरीद की बात करें तो योगी सरकार एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर किसानों से यह खरीद कर रही है। धान खरीद सत्र 2025-26 में 18 फरवरी दोपहर 12 बजे तक 12.78 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है।